

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-02 ● अंक- 22 ● भिलाई, शुक्रवार 07 अगस्त 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

आंखों के इलाज के लिए विदेश नहीं जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट ने तुणमूल कोप्रिस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह भारत में बनर्जी को आंखों की स्थिति का आकलन किए बिना उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है, ताकि यह देखा जा सके कि विदेश यात्रा आवश्यक है या नहीं। न्यायमूर्ति सीगता भट्टाचार्य ने प्रस्ताव दिया था कि बनर्जी अपनी आंखों की स्थिति का आकलन एसएसकेएम अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड से कराए ताकि जांच की जा सके कि क्या भारत में आंखों का इलाज मिल सकता है। कोर्ट ने गौर किया कि बनर्जी द्वारा उपचार का मूल्यांकन इस आलोक में करना चाहिए कि वह कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। बनर्जी भारत में ऐसे मूल्यांकन के इच्छुक नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

महाराष्ट्र में गैर-डेयरी पनीर पर एक साल के लिए प्रतिबंध

मुंबई। महाराष्ट्र की सरकार ने स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए एनालॉग यानी गैर-डेयरी पनीर के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंघे द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि अगर कोई एनालॉग पनीर बनाता या बेचता पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने की कैद या 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नकली डेयरी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा राज्य बन गया है। यह प्रतिबंध राज्य में एक साल की अवधि के लिए लगाया गया है। इसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। मुंघे ने आदेश में कहा, पूरे महाराष्ट्र में एक वर्ष की अवधि के लिए एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर का निर्माण, प्रसंस्करण, तैयारी, पैकिंग, भंडारण, वितरण, थोक बिक्री, खुदरा बिक्री, पेशकश या बिक्री के लिए प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। विभाग ने चेतावनी दी कि नुकसान की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।

सीजेपी प्रदर्शन में बड़े आतंकी हमले की थी योजना

नईदिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की पाकिस्तान की खौफनाक साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। पंजाब पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी से सीधे जुड़े 2 बड़े आतंकी माईयूल्स का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामलों में 4 नाबालिगों समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का पहला माईयूल्स अमृतसर के राजसांसी इलाके से पकड़ा गया। इस माईयूल्स में सुखमन सिंह (19) और उसके 3 नाबालिग साथी शामिल थे।

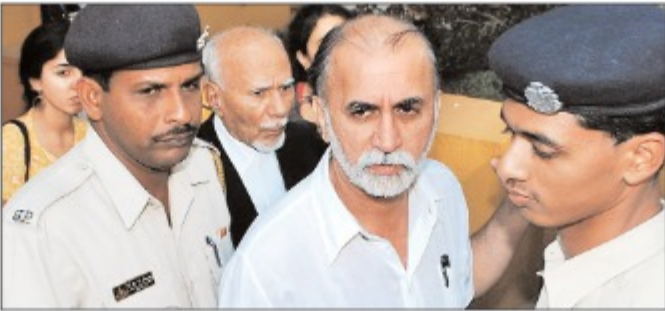
तरुण तेजपाल दोषी करार

तेजपाल को 2013 यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की सजा

नई दिल्ली/ एजेंसी

पत्रकारिता की दुनिया में कभी बड़ा नाम रहे तहलका पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल के लिए कानून का घेरा अब पूरी तरह कस चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तेजपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 2013 के उस चर्चित मामले में आया है, जिसमें एक जूनियर सहकर्मी ने उन पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए थे। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न

धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 10 साल की सजा इन अपराधों के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा है। इन धाराओं के तहत दंडित किया गया है धारा 376(2) और 376(2): विश्वास के रिस्ते और प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग कर बलात्कार करने के लिए 10 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धारा 354 ए: यौन उत्पीड़न के लिए एक साल की सजा। धारा 354बी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने के लिए तीन साल की सजा और 10,000 रुपये आरोप लगाए थे। जस्टिस डॉ. धारा 341 और 342 के तहत भी जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी,



जिसका अर्थ है कि तेजपाल को कुल 10 साल जेल में बिताने होंगे। यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान तरुण तेजपाल पर अपनी ही सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगा था। मई 2021 में मापुसा की एक सेशन कोर्ट ने तेजपाल को सभी

महत्वपूर्ण मोड़ 19 नवंबर 2013 को तेजपाल द्वारा भेजा गया एक ईमेल था। उन्होंने तहलका की तत्कालीन प्रबंध संपादक शोमा चौधरी को भेजे गए ईमेल में पीड़िता से बिना शर्त माफ़ी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि यह निर्णय की शर्मनाक चूक थी, जिसने उन्हें पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। अदालत ने इस स्वीकारोक्ति और अन्य सबूतों को आधार मानते हुए न्याय सुनिश्चित किया। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह निर्णय न केवल एक हाई-प्रोफाइल मामले का अंत है, बल्कि यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही को लेकर एक कड़ा संदेश भी है।

न्यायालय का आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को 2021 के लखीमपुर खीरी हिरा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत की शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सुरेंद्रकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने आशीष मिश्रा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की शर्तों में और राहत देने तथा पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने पैतृक स्थान पर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। मिश्रा के वकील ने अदालत से कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वह अपनी बेटियों के जन्मदिन जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं।



छत्तीसगढ़ में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

कोर्ट से आसाराम अंतरिम जमानत नहीं

एम्स रिपोर्ट के बाद 24 घंटे मेडिकल निगरानी के निर्देश

नई दिल्ली। जोधपुर में दुष्कर्म के दोषी आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया। रिपोर्ट में कहा गया कि आसाराम को फिलाहल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत है। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मांगते समय सुप्रीम कोर्ट में लॉबिंग अंतरिम जमानत याचिका की



जानकारी छिपाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आचरण पर नाराजगी जताई। अदालत ने आसाराम को अपनी पसंद का प्रशिक्षित (ट्रेड) केयरगिवर रखने की अनुमति देते हुए कहा कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत बिगड़ती है।

फैक्ट्री में काम के लिए ले जाए जा रहे 16 बच्चों का किया गया रेस्क्यू,नियोक्ता को किया गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के त्वरित हस्तक्षेप के बाद चाइल्ड हेलपलाइन और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (स्व्क) को संयुक्त टीम ने महज डेढ़ घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए बच्चों को बस से बरामद किया। मामले में एक नियोक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बच्चों को ले जाने वाले पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा को 5 अगस्त को शाम एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की ओर से सूचना मिली थी कि रायपुर से कुछ बच्चों को बस के जरिए बाल श्रम के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड हेलपलाइन के अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद संयुक्त टीम ने अभियान शुरू किया और करीब डेढ़ घंटे के भीतर बस को रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू की



गई टीम को बस में कुल 16 बच्चे मिले। इनमें 7 बच्चे 14 से 16 वर्ष आयु वर्ग के नाबालिग हैं। सभी बच्चे बैगा जनजाति से संबंधित बताए जा रहे हैं और राजनांदगांव तथा कबीरधाम जिले के रहने वाले

हैं। रेस्क्यू के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाल आश्रय गृह में रखा गया है। यहां बच्चों को काउंसिलिंग के साथ-साथ उनकी देखभाल की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चों को कचनूर स्थित मॉडर्न

एग्रो मशरूम में काम कराने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस मामले में नियोक्ता लक्ष्मण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(2), 143(3), 143(5) और 111(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल श्रम, बाल तस्करी और बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों में आयोग जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करता है।

जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे आबान

यूपी के झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत....

नई दिल्ली/ एजेंसी

उत्तर प्रदेश के झांसी में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी जान चली गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अबान अहमद अपने साथियों के साथ प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था। इसी



दौरान झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टकरा इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में अबान और उसके साथी सोनू की मौके पर ही मौत हो

गई। हादसे में घायल लोगों में मोहम्मद जैद और उमर सहित तीन लोग शामिल बताए जा रहे हैं। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पूंछ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना तेज रफ्तार, चालक के नियंत्रण खोने या किसी अन्य वजह से हुई। अबान अहमद, माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था।

लोकसभा सचिवालय के निदेशक नोएडा में फ्लैट के अंदर फांसी से लटके मिले

नई दिल्ली। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुधवार को लोकसभा सचिवालय के 40 वर्षीय निदेशक गौरव गौतम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गौतम नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केन्द्रीय विहार-2 सोसाइटी में रहते थे। उनका शव फ्लैट के अंदर छत के पंखे से लटकता हुआ था। घटना के समय गौतम की पत्नी अपने मायके गई थीं। उनके लौटने पर घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। मामले की जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौतम की पत्नी जब बुधवार को अपने मायके से लौटीं तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाते पर दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को बुलाया।

4 मंत्रियों की कमेटी तैयार

13 दिन के आंदोलन के बाद झुकी हेमंत सोरेन सरकार.....

रांची/ एजेंसी

झारखंड की राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रेडियम में छत्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले 13 दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार अब इन प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे बातचीत करने के लिए मंत्रियों की चार सदस्यीय समिति बनाई है। इस समिति में हेमंत कैबिनेट के चार मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, समिति में राज्य के



उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनु, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले, सरकार ने छात्रों से

बातचीत करने के लिए एसडीओ और एडीएम (कानून-व्यवस्था) को भेजा था। इससे पहले सरकार की ओर से रांची के एसडीओ कुमार रजत बुधवार को जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रेडियम पहुंचे। उन्होंने छात्रों से कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। पांच या सात छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भेजिए। सरकार हर मुद्दे पर बातचीत से हल निकालने को तत्पर है, लेकिन छात्रों ने भी साफ जवाब दे दिया। छात्रों ने कहा कि बातचीत होगी, लेकिन बंद कमरे में नहीं। कैमरे के सामने होगी। मीडिया की मौजूदगी में होगी। जो बात होगी।

उनका विरोध करना देश-विरोधी नहीं

मोहन भागवत बोले-जेन-जी पर आंख बंद करके भरोसा है मुझे..

मुंबई/ एजेंसी

अगर मुझे किसी एक पीढ़ी पर भरोसा करना हो, तो मैं जेन-जी पर आंख बंद करके भरोसा करूंगा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहते हुए आज की युवा पीढ़ी को हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सवालों को दबाने के बजाय उन्हें सुनना और समझना चाहिए। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बोलेते हुए भागवत ने कहा कि हर आंदोलन देश-विरोधी नहीं होता। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, एलजीबीटी समुदाय, समलैंगिक साथ पाकिस्तान और राष्ट्रीय एकता जैसे

कई मुद्दों पर भी उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। मोहन भागवत के बयान से निकलने वाले 5 बड़े संदेश जेन-जी पर पूरा भरोसा जताया। छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध को जायज बताया। शिक्षा को व्यापार बनाने का विरोध किया। एलजीबीटी समुदाय को समाज का हिस्सा बताया। राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट रहने और संवाद से समाधान निकालने पर जोर दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि उन्हें देश की नई पीढ़ी यानी जेन-जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक पीढ़ी पर भरोसा करना हो, तो वह बिना किसी संकोच के जेन-जी पर भरोसा करेंगे। भागवत के मुताबिक, आज के युवा ईमानदारी से बदलाव चाहते हैं। वे देश और समाज के मुद्दों को लेकर गंभीर हैं।



इसलिए उनकी नीयत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाल की घटनाओं की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद युवाओं

पर उनका भरोसा कायम है। मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि संवाद और असहमति भी उसकी अहम पहचान है। उन्होंने कहा कि अगर छात्र शिक्षा व्यवस्था या किसी अन्य व्यवस्था

में कमियां देखते हैं, तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। विरोध का उद्देश्य व्यवस्था को सुधारना होना चाहिए, न कि हिंसा या टकराव पैदा करना। भागवत ने कहा कि छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना चाहिए। अगर युवा बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। अपने संबोधन में भागवत ने पुरानी और नई पीढ़ी की सोच का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले लोग अधिकारियों या व्यवस्था से सवाल पूछने में झिझकते थे। लेकिन आज की जेन-जी और जेन अल्ट्रा खुलकर सवाल पूछती है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी भावनात्मक नहीं, बल्कि तार्किक जवाब चाहती है। वह सम्मान के साथ संवाद में विश्वास करती है।

शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने की मांग क्यों दोहराई?

भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय बजट का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की मांग नई नहीं है। यह लंबे समय से उठाई जाती रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में निवेश बढ़ाना समय की जरूरत है। हालांकि केवल सरकार के भरोसे बदलाव संभव नहीं है। उनके मुताबिक, समाज, स्वयंसेवी संस्थाएं और शैक्षणिक संगठन भी शिक्षा सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसी देशों के मुद्दे पर भागवत ने कहा कि जब देश किसी चुनौती का सामना कर रहा हो, तब सभी नागरिकों को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान और चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित संवर्धित होना चाहिए।

डिजिटल न्याय वितरण प्रणाली की नई गति : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में 'मीडिएशन 3.0, न्याय श्रुति एवं ICJS' पर व्यापक संयुक्त कार्यशाला आयोजित

दुर्ग। माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2026 को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला "Strengthening Digital Justice Through New Criminal Laws" में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा नवीन आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा तकनीक-संचालित न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 'मीडिएशन 3.0, न्याय श्रुति एवं ICJS' विषय पर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राज्य में न्यायिक नवाचार, संस्थागत उत्कृष्टता एवं प्रौद्योगिकी आधारित न्यायिक सुधारों को निरंतर प्रोत्साहित करने वाले माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. पी. साहू के मूल्यवान मार्गदर्शन एवं सतत प्रेरणा ने इस पहल को नई दिशा प्रदान की है। न्यायिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं न्यायिक प्रणाली की कार्यशक्ति न्यायिक कर्मचारियों को मीडिएशन 3.0, न्याय श्रुति एवं ICJS के व्यावहारिक एवं तकनीकी पहलों से अवगत करने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा इस संस्थागत पहल की परिकल्पना की गई, जिससे जिला स्तर पर डिजिटल एवं समर्पित न्याय वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सके।

कार्यक्रम का शुभारंभ कंप्यूटराईजेशन समिति के अध्यक्ष तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कोसले के स्वागत उद्घोषण से हुआ। उन्होंने कार्यशाला की विषय-वस्तु, उद्देश्य एवं उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए नवीन आपराधिक विधियों के प्रभावी



क्रियान्वयन में डिजिटल तकनीकों की भूमिका, न्यायिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण तथा न्यायालयों में प्रौद्योगिकी आधारित कार्य-संस्कृति के महत्व पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्रीमती कामिनी जायसवाल ने मीडिएशन 3.0 विषय पर अत्यंत प्रभावशाली एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी। उन्होंने मध्यस्थता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान समय में इसकी बढ़ती आवश्यकता, न्यायालयों में वैकल्पिक विवाद समाधान की भूमिका तथा भविष्य की संभावनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न व्यावहारिक उदाहरणों एवं प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित स्लाइड्स के माध्यम से विषय को अत्यंत सरल एवं सहज रूप में प्रस्तुत किया।

इसके उपरांत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी श्री रवि महोबिया ने न्याय श्रुति एवं ICJS

के संबंध में विस्तृत तकनीकी जानकारी प्रदान की। उन्होंने न्याय श्रुति एप्लिकेशन का वेबसाइट के माध्यम से लाइव प्रदर्शन करते हुए उसके विभिन्न मॉड्यूल, उपयोगिता एवं नवीन आपराधिक विधियों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रबंधन, डिजिटल अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यप्रणाली में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का विस्तारपूर्वक प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री के. विनोद कुंजर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) ने अपने मार्गदर्शनपरक उद्घोषण में कहा कि वर्तमान समय में न्यायिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का प्रभावी एवं उतरदायी उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं न्यायिक कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे मीडिएशन 3.0 को केवल एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली

के रूप में न देखें, बल्कि न्यायालयों में सौहार्दपूर्ण वातावरण, मानवीय संवेदनशीलता, संतुलित व्यवहार एवं न्यायिक दक्षता को बढ़ाने वाले प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाएं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने आचरण में शालीनता, संतुलन एवं सकारात्मक कार्य-संस्कृति बनाए रखते हुए न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जन-केंद्रित बनाने में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया।

कार्यशाला में समस्त न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों, शासकीय अधिकारियों, जिला लोक अभियोजकों, सहायक जिला लोक अभियोजकों तथा आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने डिजिटल न्याय व्यवस्था, न्याय श्रुति, ICJS, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रबंधन तथा मीडिएशन 3.0 से संबंधित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक विषयों पर सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम का प्रभावी एवं गरिमामय संचालन व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी सुश्री प्रियंका गोस्वामी द्वारा किया गया।

यह कार्यशाला जिला न्यायालय, दुर्ग द्वारा तकनीक-संचालित, पारदर्शी, दृढ़ एवं भविष्य उन्मुख न्याय वितरण प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल सिद्ध हुई। यह कार्यक्रम न केवल न्यायिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं न्यायिक कर्मचारियों के क्षमता-विकास का प्रभावी मंच बना, बल्कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास के रूप में भी स्थापित हुआ।

विधायक रिकेश Gen Z के लिए 10 अगस्त को शुरू करेंगे 16 योजनाएं, Gen Z के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं की अनूठी पहल

भिलाई नगर। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने युवाओं और नागरिकों को शिक्षा, रोजगार तथा डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की पहल की है। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा, रोजगार, डिजिटल सुविधा और व्यक्तिगत विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

इस पहल के तहत युवाओं के लिए निःशुल्क लॉगिन लाइसेंस, जन्मदिन पर मुवी टिकट, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क वाई-फाई तथा 12वीं पास युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 10 हजार रुपये वेतन वाली नौकरी की व्यवस्था सहित कुल 16 योजनाएं जेनजी के लिए प्रारंभ की जा रही हैं। इन योजनाओं के लिए 10 अगस्त को लोकांगन परिसर में जेनजी फार्म भर सकेंगे।

आपको बता दें कि बीए, बीकाम और बीएससी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कॉचिंग तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क



प्रशिक्षण की भी योजना है। कंप्यूटर सीखने के इच्छुक बच्चों को भी निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं में बच्चों के लिए दीपावली पर विशेष उपहार तथा जन्मदिन पर पांच लीटर पेट्रोल और केक देने की पहल भी शामिल है। कोटा, राजस्थान में कॉचिंग करने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। वैशाली नगर विधानसभा के रहवासियों के लिए श्री सेन की योजनाओं में जेनजी के लिए देश के किसी भी धार्मिक स्थल के दर्शन के

लिए जाने वाले पात्र लोगों को एक तरफ का ट्रेन किराया निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल है। इन योजनाओं का लाभ वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पात्र Gen Z युवाओं को मिलेगा। इसके आलावा डिजिटल युग में नागरिकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने विधायक रिकेश सेन के जन्मदिवस के अवसर पर निःशुल्क कंप्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम में 30 से 60 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित महिला एवं पुरुष शामिल हो सकेंगे।

बलौदाबाजार में महानगरों की तर्ज पर बिछेगी पाइपलाइन, जल्द मिलेगी घर-घर पीएनजी रसोई गैस सुविधा



बलौदाबाजार। महानगरों की तर्ज पर अब बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के निवासियों को भी रसोई गैस सिलेंडरों के झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा 'सिटी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट' के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में जिलेवासियों को सीधे पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित और निर्बाध प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति मिलेगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना की प्रगति को लेकर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को जिला कार्यालय में एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड के

प्रतिनिधियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति का जायजा लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करें और निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें, ताकि आम नागरिकों को जल्द से जल्द इस आधुनिक सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन बिछाने में गड़बड़ खोदने के लिये लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग अथवा पंचायत से एनओसी की जरूरत होने पर शीघ्र जारी किया जाए। प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों ने बताया कि पाइप लाइन बिछाने कार्य रायपुर से शुरू कर दिया गया है जो

जिले के सिमगा तक पहुंच गया है। वर्तमान में विकासखण्ड सिमगा के ग्राम केसदा में काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि पीएनजी का कनेक्शन पाईप लाईन के आस पास के औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्कूल, अस्पताल व शहरों में दिया जाएगा। पाईप लाइन घर के सामने से गुजरेगी जिसमें बीच- बीच में कनेक्शन बॉक्स रहेगा जहां से घर के रसोई तक कनेक्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएनजी बहुत ही सुरक्षित है जिसमें ब्लास्ट होने की कोई खतरा नहीं होता, मीटर के अनुसार बिल का भुगतान करना होगा। पाइपलाइन गैस सेवा शुरू होने से आम जनता को समय पर सिलेंडर रीफिलिंग की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही यह सुविधा आर्थिक रूप से कफायती और पर्यावरण व सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद अनुकूल साबित होगी। बैठक में एचसीजी के प्रतिनिधियों ने आभार किया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिले में मुख्य नेटवर्क और घरेलू कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

भाजपा महिला मोर्चा भिलाई ने वीर जवानों को भेजा स्नेह का संदेश

सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भिलाई से 30 हजार से ज्यादा राखियां, मिट्टी और स्नेह पत्र भेजे

भिलाई। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाजपा महिला मोर्चा भिलाई द्वारा ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 0.4 का सफल आयोजन किया। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के मार्गदर्शन और जिलाध्यक्ष स्वीटी कौशिक के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान, अपनाना और राष्ट्रभक्ति को भावना को सशक्त करना रहा। अभियान के अंतर्गत भिलाई की



माताओं और बहनों ने मिलकर 30,000 से अधिक रक्षा सूत्र तैयार कर देश की सीमाओं पर तैनात गवीर जवानों के लिए भेजे। राखियों के साथ अपने आंगन की एक भिलाई में भूतपूर्व सैनिकों की उपस्थिति में जवानों को राखियां भेजी गईं। चुटकी मिट्टी तथा बहनों द्वारा

लिखे गए आत्मीय संदेश भी प्रेषित किए गए, ताकि देश की रक्षा में जुटे सैनिकों तक अपने घर-परिवार का स्नेह और आशीर्वाद पहुंच सके। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि राष्ट्रक्षा में समर्पित सैनिकों के प्रति सम्मान और

कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। प्रत्येक रक्षा सूत्र देशवासियों के विश्वास, प्रेम और सैनिकों के प्रति अटूट सम्मान का प्रतीक है। यह आयोजन राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सहभागिता और सैनिक सम्मान की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का प्रेरणादायी प्रयास रहा। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन की विशेष उपस्थिति रही। अभियान के प्रमुख सहयोगी एवं भूतपूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप राणा सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भी सहभागिता निभाई, जिससे कार्यक्रम का गौरव और बढ़ गया। इस अवसर पर निर्मला नायडू, प्रभा साहू, पुष्पा रे, स्वाति गुप्ता, स्नेहा शुक्ला, सरला आचार्य, पुष्पलता कर, सबुजा

देवी, सरोज सिंह, अनुपमा शुक्ला, पुनम सिंह, ममता भारद्वाज, यशोदा निर्मलकर, सुरेखा देशमुख, पद्मिनी साहू सहित अन्य उपस्थित रहे। उदाई मंडल की महिलाओं ने एक हजार राखियां वीरों के लिए भेज झर भाजपा उदाई मंडल और महिला मोर्चा की ओर से भी एक राखी जवानों के नाम अभियान के तहत 1000 राखियां सैनिक भाइयों के लिए भेजी गईं। राखियों के साथ सैनिकों के नाम स्नेह भरे पत्र भी भेजे। उदाई मंडल अध्यक्ष शीतला ठाकुर ने कहा कि उदाई मंडल की बहनों ने राखियां एकत्रित कर देशभक्ति का परिचय दिया है। हमें गर्व है कि हमारी बहनें इस तरह राष्ट्र सेवा में आगे आ रही हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भारत

फसल बीमा समय की वृद्धि कृषक हितेषी संवेदनशील निर्णय-विजय मोटवानी

धमतरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की निश्चित तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 14 अगस्त किए जाने पर नगर निगम के लोक निर्माण विभाग अध्यक्ष विजय मोटवानी द्वारा स्वागत करते हुए इसे किसानों के हितकारी, महत्वपूर्ण कदम एवं निर्णय बताया है। मोटवानी ने कहा है कि किसान अपनी मेहनत को जब फसल के रूप में पूरा पूंजी के



साथ लगा देता है तो कई बार उन्हें हताशा एवं परेशानियों का सामना किसी प्रकोप के कारण करना पड़ता

है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समृद्ध करके कृषि को उन्नत बनाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वरदान स्वरूप फसल बीमा योजना की सौगात दी है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सार्थक एवं सशक्त कदम है।

कामता चितावर धाम में बूढ़ादेव मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा, ध्रुव समाज में उत्साह का माहौल



तिल्दा-नेवरा/सिमगा। सिमगा विकासखंड के समीप स्थित ग्राम कामता के चितावर धाम में सोमवार को ध्रुव समाज के तत्वावधान में बूढ़ादेव मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा एवं स्थापना समारोह श्रद्धा, आस्था और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पदाधिकारी, वरिष्ठजन, महिलाएं, युवा एवं श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे परिसर में भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुआ। विद्वान आचार्यों के सान्निध्य में धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए बूढ़ादेव मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न करई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धाभास से

पूजा-अर्चना कर समाज की सुख-समृद्धि, आपसी एकता, सामाजिक उन्नति तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। जय बूढ़ादेव के जयघोष से पूरा चितावर धाम भक्तिमय वातावरण में सजबोर हो गया। समारोह में उपस्थित समाज के वरिष्ठजनों ने कहा कि बूढ़ादेव ध्रुव समाज के आराध्य देव हैं और उनकी स्थापना समाज की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक मूल्यों को नई मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे समाज में संपन्न, भाईचारा और सामाजिक एकता की भावना भी सुदृढ़ होती है। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने बूढ़ादेव एवं बूढ़ी दाई की

विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महिलाओं और युवाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी निभाई। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजनाया गया था, जिससे आयोजन की भव्यता और अधिक बढ़ गई। धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसके साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के सफल संचालन में ध्रुव समाज के पदाधिकारियों, युवाओं एवं प्राणीणों का सहान्वीय सहयोग रहा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसकी समाजजनों ने भरपूर-भरपूर प्रशंसा की।

सार्थक स्कूल की कमजोर दृष्टि वाली दो विशेष बालिकाओं को मिले नए चश्मे

धमतरी। सार्थक स्कूल धमतरी में अध्ययनरत दो विशेष बालिकाओं की दृष्टि अत्यंत कमजोर होने के कारण उन्हें दैनिक जीवन, अध्ययन एवं प्रशिक्षण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनकी आवश्यकता को संवेदनशीलता से समझते हुए धमतरी के समाजसेवी एम एल चौराईया के पुत्र आशीष चौराईया एवं पुत्रवधु नमिता चौराईया ने दोनों बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के नए चश्मे भेंट किए, ताकि वे स्पष्ट रूप से देख सकें, आत्मविश्वास के साथ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ने के अपने स्वप्नों को नई उड़ान दे सकें। इस अवसर पर प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय पंजवानी ने दोनों बालिकाओं की निःशुल्क नेत्र जांच कर उचित पावर के चश्मों का परामर्श दिया। नेत्र जांच के अवसर पर डॉ. वंदना पंजवानी का भी सहयोग रहा। सार्थक स्कूल की अध्यक्ष डॉ. सूरिता देशी ने कहा कि समाज में ऐसे संवेदनशील एवं सेवा-धारी लोगों के कारण ही विशेष बच्चों के जीवन में आशा की नई किरण जगती है। किसी बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग देना केवल दान नहीं, बल्कि उसके भविष्य को



संवारने का श्रेष्ठ प्रयास है। चौराईया दम्पति ने कहा बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और उनकी आँखों में नई चमक देखना हमारे लिए सबसे बड़ा संतोष है। यदि हमारे छोटे-से सहयोग से इन बच्चियों का जीवन थोड़ा भी सहज और उज्ज्वल बनता है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्यों में हमारा सहयोग निरंतर बना रहेगा। इस अवसर पर संस्था की सचिव स्नेहा राठौड़ तथा प्रशिक्षक मैथिली गोड़े, देविका दीवान, कोशल्या यादव एवं काजल रजक सुनैना गोड़े ने सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के ऐसे सहयोग से विशेष बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है।

संक्षिप्त समाचार

रामानुजगंज में हाथी दांत तस्करी का अंतर्राज्यीय गिरोह बेनकाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में वन विभाग और वन्यजीव अपराध नियंत्रण एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय हाथी दांत तस्करी गिरोह का भंडाभेड़ किया है। टीम ने रामानुजगंज स्थित आमंत्रण धर्मशाला में छापा मारकर हाथी के जबड़े सहित तीन नग हाथी दांत बरामद किए और मौके से झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, वनमंत्री केदार कश्यप के निर्देशन तथा वरिष्ठ अधिकारियों एवं वनमंडलाधिकारी बलरामपुर के मार्गदर्शन में वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 3 अगस्त को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (मध्य क्षेत्र, भोपाल), राज्य उड़नदस्ता दल रायपुर और वनमंडल बलरामपुर की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि रामानुजगंज के आमंत्रण धर्मशाला के कमरा नंबर-205 में कुछ सदस्य लोग हाथी दांत की खरीद-फोखत के लिए ठहरे हुए हैं। सूचना पर तत्काल छापा मारकर तलाशी ली गई, जिसमें एक बैग से जबड़े सहित तीन हाथी दांत बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान झारखंड के पलामू निवासी संतोष कुमार विश्वकर्मा (42), रामानुजगंज निवासी अजय कुमार गुप्ता (49) तथा सतेन्द्र कुमार रजक (50) के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने हाथी दांत की तस्करी में अपनी सलिप्तता स्वीकार की है। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21972/11 दर्ज कर वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 48(क), 50, 51 और 52 के तहत कार्रवाई की है। मंगलवार को तीनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामानुजगंज की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वन विभाग मामले की विस्तृत जांच कर तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटा है।

मंडल अध्यक्ष बताकर दो भाइयों ने किया जमकर हंगामा भेजे गए जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शराब के नशे में धुत दो सगे भाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। मुड़पार स्थित कुआंभटा शराब दुकान के चखना सेंटर में पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि एक युवक ने खुद को मंडल अध्यक्ष बताते हुए दुकानदारों पर रौब झाड़ा और विवाद बढ़ने के बाद अपने भाई को बुला लिया। दोनों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से दुकानदारों के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों युवक पुलिस के साथ बहस और बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। शराब दुकान परिसर में हुई मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक, दोनों भाई शराब दुकान के पास स्थित चखना सेंटर में पहुंचे थे। चखना खाने के बाद जब दुकानदार ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कथित तौर पर भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दुकानदार और युवकों के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने खुद को मंडल अध्यक्ष बताते हुए दुकानदारों पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर युवक ने अपने दूसरे भाई को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने दुकानदारों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया। शराब दुकान परिसर में दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिससे मौके पर अपरा-तफरी का माहौल बन गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई।

आधी रात को मड़ई पहुंचकर लोनर हाथी ने फिर ढहाया गाय मकान

रायपुर। जिले में लोनर हाथियों का आतंक लगातार जारी है, जहां कटघोरा वनमण्डल के एतमानगर रेंज के बंजारी से आधीरात को पहुंचे लोनर हाथी ने मड़ई गांव में बुधनराम नामक ग्रामीण के मकान को ढहा दिया। वहीं करतला रेंज के बड़मगर में एक किसान की जान लेने वाला दतैल हाथी अभी भी क्षेत्र में मण्डरा रहा है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। जानकारी के अनुसार जंगलों में इन दिनों 5 दर्जन से अधिक हाथी विभिन्न स्थानों का विचरण कर रहे हैं, जिनमें से 52 हाथी कटघोरा वनमण्डल में सक्रिय हैं जबकि 11 हाथी कोरबा के जंगल में है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथियों की निगरानी को लेकर विभाग सतर्क है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मुनादी कराकर हाथियों की उपस्थिति को सूचना दी जा रही है। ग्रामीणों को व्हाट्सप एप ग्रुप बनाकर हाथियों की जानकारी निरंतर दी जा रही है। हाथियों की सटीक लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। सजग एप के प्रयोग से ग्रामीणों को जोड़ गया है जिससे उन्हें हाथी विचरण की निरंतर सूचना मिल रही है। हाथी मित्र दल' प्रतिदिन गश्त पर तैनात है। साथ ही, वन परिक्षेत्र के समस्त मैदानी कर्मचारियों को रोस्टर वार 24-7 रात्रि रायत एवं निगरानी ड्यूटी लगाई गई है। विद्युत विभाग को भी हाथियों के विचरण की जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है एवं हाथी मॉनिटरिंग में उनका सहयोग लिया जा रहा है।वर्तमान में कोरबा वन मंडल अंतर्गत 2 लोनर (अकेले) हाथी एवं 9 हाथियों का एक अलग दल (कुल 11 हाथी) विभिन्न क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से कहा है कि हाथियों के विचरण क्षेत्र में अल सुबह या देर शाम अकेले व असुरक्षित रूप से न निकलें। हाथियों से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उनके करीब जाने या उन्हें छेड़ने का प्रयास न करें। वन विभाग द्वारा की जा रही मुनादी और चेतावनी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि किसी भी अग्रिय घटना से बचा जा सके।

मछली बीज उत्पादन से किसान रयतु राम ने लिखी सफलता की नई कहानी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के किसान नवाचारों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर जिले के ग्राम पंचायत सिवनी (हिरलाभाट्या) निवासी प्रगतिशील किसान रयतु राम ने मछली बीज (स्पॉन) उत्पादन अपनाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। कम समय में बेहतर आय अर्जित कर उन्होंने यह साबित किया है कि आधुनिक तकनीक और विभागीय मार्गदर्शन के साथ मत्स्यपालन किसानों के लिए लाभकारी आजीविका का सशक्त माध्यम बन सकता है। रयतु राम ने अपनी कुल 5 एकड़ कृषि भूमि में से लगभग एक एकड़ क्षेत्र में बने तालाब में इस वर्ष मछली बीज उत्पादन का कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस सीजन में तालाब में लगभग 30 पैकेट स्पॉन डाले गए। अब तक वे लगभग 60 किलोग्राम मछली बीज 500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच चुके हैं, जिससे उन्हें 30 हजार रूपए की आय प्राप्त हुई है। तालाब में अभी भी 40 से 50 किलोग्राम मछली बीज उपलब्ध है, जिसकी निम्नी से उन्हें 20 से 25 हजार रूपए अतिरिक्त आय मिलने की उम्मीद है।

राजधानी

वन महोत्सव-2026 का हुआ शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी माँ के नाम पर लगाया पीपल का पौधा

■ पीपल फॉर पीपुल’ अभियान के तहत 15 एकड़ में लगाए गए 2500 से अधिक पीपल के पौधे

■ एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान से जुड़कर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लें : मुख्यमंत्री तिष्णु देव साय

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज वन महोत्सव-2026 का शुभारंभ करते हुए नया रायपुर में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी माँ के नाम पर पीपल का पौधा लगाकर प्रदेशव्यापी ‘पीपल फॉर

पीपुल’ अभियान को शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में 2500 से अधिक पीपल के पौधे रोपे गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों को जीवनदाता माना गया है और पीपल का वृक्ष विशेष रूप से आस्था, आध्यात्मिक चेतना तथा पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। यह वृक्ष सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में माना जाता है और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण



दिवस 5 जून 2024 से प्रारंभ हुआ ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान आज जनआंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को मातृ सम्मान की भावना से जोड़ा गया है, जिससे समाज में प्रकृति के प्रति आत्मीयता और जिम्मेदारी का भाव विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान को व्यापक

जनसमर्थन मिला है। पिछले दो वर्षों में पेड़ माँ के नाम’ अभियान आज जनआंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को मातृ सम्मान की भावना से जोड़ा गया है, जिससे समाज में प्रकृति के प्रति आत्मीयता और जिम्मेदारी का भाव विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान को व्यापक

महतारी वंदन योजना से पूर्णिमा के हाथों में आया आर्थिक संबल,बढ़ा आत्मविश्वास

■ नियमित सहायता से परिवार की जरूरतें पूरी करना हुआ आसान

रायपुर/ संवाददाता

गृहणी पूर्णिमा मानिकपुरी के लिए एक समय ऐसा भी था, जब घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। परिवार की सीमित आय में बच्चों की पढ़ाई, कॉपी-किताब, घरेलू सामान और अचानक होने वाले इलाज के खर्च की व्यवस्था करना कई बार मुश्किल हो जाता था। कबीरधाम जिले के ग्राम जीतायेला की रहने वाली पूर्णिमा ऐसे में उन्हें छोटी-



मिलने वाली राशि से ये सभी जरूरी काम समय पर हो जाते हैं। इससे परिवार का मासिक बजट भी संतुलित रहता है और आर्थिक दबाव काफी कम हो गया है। वे मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अब मुझे छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों की पढ़ाई हो, घर का जरूरी सामान हो या दवा का खर्चकूहर महीने मिलने वाली यह राशि मेरे परिवार के लिए

बहुत बड़ा सहारा बन गई है। सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब मैं भी परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी भागीदारी निभा पा रही हूं। पूर्णिमा मानिकपुरी ने बताया कि इस योजना ने उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास भी दिया है। अब उनके पास अपनी जरूरतों और परिवार की आवश्यकताओं के लिए स्वयं की राशि रहती है। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा है और वे बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों को भी पूरा कर पा रही हैं। वे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन गई है।

एक ही जमीन दो बार बेचकर लाखों की टगी

रायपुर। जिले की चांपा पुलिस ने पहले से बेची जा चुकी जमीन को दोबारा बेचकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336, 338 एवं 340(2) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, रामगोपाल यादव उर्फ ननकीदाऊ (58 वर्ष), निवासी जगदल्ला, चांपा ने अपनी नाम दर्ज भूमि का सौदा गौकरण पटेल निवासी कोटाडबरी से 6 लाख 350 रुपये में किया था। तहसील डिकेश्वर कुमार साहू ने 100 रुपये के स्टाम्प पर इकरारनामा तैयार किया गया। सौदे के दौरान 50 हजार रुपये नकद अग्रिम और बाद में 5 लाख रुपये चेक के माध्यम से आरोपी एवं उसके पुत्र को दिए गए।

अनुसार, स्वीकृत कार्यों में विकासखंड भैयाथान के 36 गांवों के लगभग 109 मोहल्लों/पारों, विकासखंड ओडुगी के 32 गांवों के लगभग 68 मोहल्लों/पारों तथा विकासखंड सूरजपुर के 29 गांवों के लगभग 53 मोहल्लों/पारों में विद्युत विस्तार किया जाएगा। यह परियोजना विशेष रूप से उन ग्रामीण और जनजातीय बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां अब तक पर्याप्त विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बिजली पहुंचने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्य, पेयजल के व्यवस्था, कृषि आधारित गतिविधियों तथा ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य विकास की रोशनी को अंतिम छोर तक पहुंचाना है।



ग्राम उत्कर्ष अभियान' के अंतर्गत भटगांव विधानसभा क्षेत्र के 97 गांवों में विद्युत विस्तार कार्य स्वीकृत किया गया है। लगभग 11.62 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत इस परियोजना के माध्यम से सूरजपुर जिला के दूरस्थ गांवों और मोहल्लों तक विद्युत सुविधा पहुंचाई जाएगी, जिससे हजारों ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के

■ 11.62 करोड़ रुपये की लागत से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचेगी बिजली

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी दिशा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधानसभा की विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निशाने प्रयासों से 'धरती आबा जनजातीय

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया ने समावेशी ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए छ्तीसगढ़ सरकार के साथ की साझेदारी

छोटे किसान की महिलाएँ ही ग्रामीण बदलाव की असली प्रेरक हैं

■ ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांज़िशन हरित आर्थिक बदलाव पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जलवायु-अनुकूल और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के रास्ते बताए गए

रायपुर/ संवाददाता

छठे 'इंडिया रूरल कोलोक्वी' (भारत ग्रामीण संगोष्ठी) के छत्तीसगढ़ चैयर की शुरुआत इस जोरदार अपील के साथ हुई कि छोटे किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों को ग्रामीण बदलाव की नींव के तौर पर पहचाना जाए। टीआरआई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच यह सहयोग पूरे राज्य में समावेशी और सामुदायिक नेतृत्व में होने वाले ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

रायपुर में गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के सचिव और 'गुड गर्नेस एंड कन्वर्जेंस' विभाग के सचिव, राहुल भगत ने कहा, छोटे किसान और स्वयं-सहायता समूहों की महिलाएँ ग्रामीण बदलाव की असली प्रेरक हैं। पहला कदम उठाने का उनका साहस असंख्य लोगों को बदलाव लाने वाला (चेंजमेकर) बनने के लिए प्रेरित करता है। इस चर्चा में नया रायपुर के ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और विकास कार्यों से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का काम किया गया। इससे पता चला कि कैसे मजबूत ज़मीनी नेतृत्व, जवाबदेह संस्थान और सामुदायिक ज्ञान मिलकर ग्रामीण छत्तीसगढ़ वाले संस्थानों को ग्रामीण बदलाव की नींव के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 'ग्रीन इकोनॉमिक पाथवेज़ - छत्तीसगढ़' स्टडी रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें जलवायु-अनुकूल और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य



भाषण देते हुए, पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री कि टिकाऊ ग्रामीण विकास ज़मीनी स्तर के बीच तालमेल को फ़िर से स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जहाँ कभी बदलाव मुश्किल लगता था, वहीं प्यार और सच्ची कोशिशों से बदलाव आया। हर ईसान प्यार चाहता है और उन्हें बस ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उन्हें सच में समझे। मजबूत स्थानीय संस्थानों के महत्व पर बात करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के

सचिव भीम सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि टिकाऊ ग्रामीण विकास ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, हर सरकारी योजना का असली क्रियान्वयन गांव के स्तर पर होता है। अगर गाँव के संस्थान मजबूत नहीं होंगे, तो विकास की गति सीमित ही रहेगी। वर्ष 2016 में स्थापित ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) ग्रामीण समुदायों के साथ मिलकर स्थानीय नेतृत्व पर आधारित समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए

कार्यस्थल अथवा आसपास उपलब्ध ख़ाली भूमि पर अपनी माँ के नाम एक पौधा अवश्य लगाएँ और उसके पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी निभाएँ। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पौधा आने वाले समय में स्वच्छ वायु, शुद्ध वातावरण और सुरक्षित भविष्य का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि बढ़ता तापमान, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव पूरी दुनिया के सामने गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे समय में वृक्षारोपण सबसे प्रभावी और सरल उपायों में से एक है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन संभव है। मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने प्रतिदिन एक पौधा लगाने का आजीवन प्रण लिया है।

पैडी ट्रांसप्लांटर से किसान डिकेश्वर साहू ने घटाई लागत,बढ़ाई उत्पादकता



■ 25 एकड़ में धान की खेती, प्रति एकड़ लगभग 7 हजार रुपए की बचत के साथ समय और श्रम की हुई बचत

■ आधुनिक कृषि तकनीक से बदली खेती की तस्वीर

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी और किफायती बना रहे हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती में लागत कम होने के साथ उत्पादकता भी बढ़ रही है। इसी दिशा में बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम खल्लारी निवासी प्रगतिशील किसान श्री डिकेश्वर कुमार साहू ने पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई मशीन) के उपयोग से खेती में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसान डिकेश्वर साहू लगभग 25 एकड़

भूमि में धान की खेती करते हैं। पहले धान रोपाई के समय उन्हें मजदूरों की कमी और बढ़ती मजदूरी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई करने पर प्रति एकड़ लगभग 8 हजार रुपये का खर्च आता था। कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्होंने पहले हाथ से चलने वाला पैडी ट्रांसप्लांटर अपनाया। इससे मिले सकारात्मक परिणामों के बाद उन्होंने इस वर्ष छह लाइन वाला आधुनिक पैडी ट्रांसप्लांटर खरीदा, जिससे खेती और अधिक आसान एवं लाभकारी हो गई। डिकेश्वर साहू ने बताया कि आधुनिक मशीन के उपयोग से धान रोपाई की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले जहां प्रति एकड़ लगभग 8 हजार रुपए खर्च होते थे, वहीं अब मशीन के माध्यम से यह खर्च घटकर लगभग 1 हजार रुपए प्रति एकड़ रह गया है। इस प्रकार उन्हें प्रति एकड़ लगभग 7 हजार रुपए की बचत हो रही है। साथ ही 25 एकड़ में रोपाई का कार्य कम समय में पूरा हो जाने से श्रम और समय दोनों की बचत हो रही है। पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करने पर पौधों के बीच समान दूरी बनी रहती है, जिससे प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, पानी और पोषक तत्व मिलते हैं।



संपादकीय

हाईवे बढ़े, हादसे भी बढ़े- 2025 में 5.13 लाख सड़क दुर्घटनाएं

सरकार अब ईंधन की खपत और वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन सड़क हादसों के मूल प्रश्न पर ध्यान कम ही दिया जा रहा है।दुर्घटनाओं के इन आंकड़ों से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण ही प्राथमिकता है, सुरक्षा के पहलू का उसके लिए कोई महत्त्व नहीं है? सड़क एवं परिवहन

सुविधाओं का विकास किसी भी देश की प्रगति, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक उत्थान की रीढ़ होता है। व्यापार को गति देने, दूरदराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने और आम जनजीवन को सरल बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। भारत में भी नई सड़कों के निर्माण और पहले से बने मार्गों के चौड़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि विकास के इस पथ पर सुरक्षित सफ़र की प्रतिबद्धता पीछे क्यों छूटती जा रही है?एक

तरफ केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में सड़क दुर्घटनाएं साल-दर-साल बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बीते गुरुवार को लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए गए, वे स्थिति के भयावह होने की ओर इशारा करते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, देश में वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में 5.3 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

इस दौरान 5.13 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिनमें 1.83 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई।दुर्घटनाओं के इन आंकड़ों से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण ही प्राथमिकता है, सुरक्षा के पहलू का उसके लिए कोई महत्त्व नहीं है? कहने को सरकार की ओर से सड़क हादसों को कम करने के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम और विशेष अभियान शुरू किए गए हैं, फिर क्या वजह है कि

सड़कों पर लोगों की जान जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।पिछले वर्ष देश में वाहनों की तेज रफ़तार के कारण सबसे ज्यादा 82 हजार से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो कुल सड़क हादसों का लगभग सोलह फीसद है। इस मामले में देखा जाए, तो राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्र की सड़कों पर जगह-जगह वाहनों की गति मापने के लिए सीसीटीवी और दूसरे यंत्र लगाए गए हैं। ऐसे में अगर आज भी सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं वाहनों की तेज

गति के कारण ही हो रही हैं, इसे किस तरह देखा जाएगा। जाहिर है कि जब किसी व्यवस्था की सही तरीके से निगरानी, देखरेख और उसके आधार पर ईमानदारी से सुधार की दिशा में कार्य नहीं होगा, तो सकारात्मक नतीजे की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है।सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि गलत दिशा में वाहन चलाने और लेने के नियमों का पालन न करने के कारण पिछले वर्ष करीब चार हजार सड़क दुर्घटनाएं हुईं।

आंदोलन की संस्कृति: अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी आवश्यक

(ललित गर्ग)

आज आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन की संस्कृति पर पुनर्विचार किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की ऐसी परंपरा विकसित की थी, जिसमें नैतिक बल सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह में विरोध था, परंतु वैमनस्य नहीं। संघर्ष था, परंतु हिंसा नहीं। दृढ़ता थी, परंतु अराजकता नहीं।

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संवाद, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं का जीवंत तंत्र है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार प्राप्त है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार कभी भी हिंसा, अराजकता, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश या सुरक्षा बलों पर हमले का लाइसेंस नहीं बन सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह विरोध को भी सम्मान देता है, किंतु विरोध की भी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। हल के वषों में कुछ आंदोलनों ने यह गंभीर प्रश्न खड़ा किया है कि क्या लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में कानून और व्यवस्था को चुनौती देना स्वीकार्य हो सकता है? यदि कोई प्रदर्शन बैरिकेड तोड़ने, पुलिस पर हमला करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थान की ओर जबरन बढ़ने का प्रयास सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे केवल भूकदर्थक बनी रहें। राज्य का पहला दायित्व नागरिकों की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्लेटेड गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए यह कहना कि अस्वाभारण परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसी संतुलित दृष्टिकोण का परिचायक है। न्यायालय ने किसी भी प्रकार के असीमित बल प्रयोग को उचित नहीं उहाराया, बल्कि यह स्पष्ट संकेत दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के पास आवश्यक साधन भी होने चाहिए। यदि सुरक्षा बलों से हर प्रभावी उपाय छीन लिया जाएगा, तो हिंसक भीड़ पर नियंत्रण कैसे स्थापित होगा? यह प्रश्न केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार मिल जाने चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक कार्यवाई न्यायिक समीक्षा और जवाबदेही के दायरे में रहती है। यदि कहीं बल प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ हो, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जांच का आधार तथ्य होने चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं। जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों की पीड़ा सुनी जानी चाहिए, उसी प्रकार घायल हुए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों का पक्ष भी उतनी ही गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन की संस्कृति पर पुनर्विचार किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की ऐसी परंपरा विकसित की थी, जिसमें नैतिक बल सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह में विरोध था, परंतु वैमनस्य नहीं। संघर्ष था, परंतु हिंसा नहीं। दृढ़ता थी, परंतु अराजकता नहीं। दुर्भाग्य से आज कुछ आंदोलनों में संवाद की जगह टकराव, संघर्ष की जगह उग्रता और तर्क की जगह भीड़ की शक्ति को महत्व दिया जाने लगा है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में परिवर्तन सड़क पर पत्थर फेंकने से नहीं, बल्कि विचार, संघर्ष, जनजागरण और संवैधानिक प्रक्रियाओं से आता है। यदि हर असहमति हिंसक रूप ले लेगी, तो सबसे अधिक नुकसान उठनीं युवाओं का होगा, जिनके

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संवाद, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं का जीवंत तंत्र है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार प्राप्त है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार कभी भी हिंसा, अराजकता, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश या सुरक्षा बलों पर हमले का लाइसेंस नहीं बन सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह विरोध को भी सम्मान देता है, किंतु विरोध की भी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं।

भविष्य के नाम पर आंदोलन किए जाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन और उत्तरदायित्व से होती है। यदि यह मान लिया जाए कि किसी राजनीतिक दल या उसके समर्थकों द्वारा आयोजित आंदोलन में कुछ असामाजिक और हिंसक तत्वों ने प्रवेश कर उसे अराजक दिशा देने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में सरकार का प्राथमिक दायित्व कानून-व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। समय रहते प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई, भले ही

अंततः लोकतंत्र ही कमजोर होता है। सरकारों को भी यह आत्ममंथन करना चाहिए कि जनआक्रोश की स्थितियां क्यों बनती हैं। संवाद के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। पारदर्शी निर्णय, समय पर संवाद और शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था अनेक आंदोलनों को उग्र होने से पहले ही शांत कर सकती है। लोकतंत्र में शासन का अर्थ केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि विश्वास अर्जित करना भी है।

भविष्य के लिए कुछ स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए।



उससे कुछ अधिग्र घटनाएं हुई हों, व्यापक अराजकता और राष्ट्रीय संस्थानों को संभावित क्षति से बचाने के उद्देश्य से देखी जा सकती है। साथ ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह भी अपेक्षित है कि विपक्ष जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंसा और तोड़फोड़ से स्पष्ट दूरी बनाए तथा वैध मांगों के समर्थन और अवैध कृत्यों के विरोध के बीच स्पष्ट रेखा खींचे। लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होता है जब सरकार कानून के शासन का पालन करे, विपक्ष जिम्मेदार आचरण करे और आंदोलन संविधान की मर्यादाओं एवं शांतिपूर्ण तरीकों के भीतर संचालित हों।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी दल का यह दायित्व है कि वह जनभावनाओं को सकारात्मक दिशा दे। यदि कोई राजनीतिक संघटन या उसके समर्थक आंदोलन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ या कानून हाथ में लेने को प्रोत्साहित करते हैं, तो उसकी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। विपक्ष लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है, लेकिन उसका धर्म केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना भी है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा जनआंदोलन का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, तो

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ-साथ विश्वगुरु बनने की दिशा में भी अग्रसर है। ऐसे समय में हमें विरोध की भी ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी जो विश्व के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करे। हमारे आंदोलन व्यवस्था को तोड़ने के नहीं, व्यवस्था को बेहतर बनाने के माध्यम बनें। हमारे प्रदर्शन राह को विभाजित करने के नहीं, लोकतांत्रिक चेतना को समृद्ध करने के साधन बनें। अंततः यह स्मरण रखना होगा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब कर्तव्यों का भी समान रूप से पालन किया जाए। यदि आंदोलन संविधान की मर्यादाओं में रहकर होंगे, तो सरकार भी अधिक उत्तरदायी बनेगी और लोकतंत्र भी अधिक सशक्त होगा। भारत को ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता है जो व्यवस्था को चुनौती देने के बजाय उसे सुधारने की प्रेरणा दें। जो युवाओं को उग्रता नहीं, उत्तरदायित्व सिखाएं और जो राष्ट्रहित को दलगत हितों से ऊपर रखकर लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व, अनुशासित तथा जनोन्मुख बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।

परमाणु आत्मनिर्भरता- भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक तकत और वैश्विक नेतृत्व की नई नींव

(विजन कुमार पांडेय)

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का भी आधार बन चुकी है। बदलती वैश्विक राजनीति, तकनीकी प्रतियस्धा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बढ़ती निर्भरता ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन देशों के पास अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता है, वही भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले सात दशकों में ऐसी ही क्षमता विकसित की है। मगर प्रश्न यह है कि क्या देश अपनी इस उपलब्धि को नीति-निर्माण के केंद्र में रख पा रहा है या विदेशी तकनीक का आकर्षण अभी भी स्वदेशी आत्मविश्वास पर भारी पड़ रहा है?

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही। दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन, उन्नत उपकरणों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच लगभग बंद हो गई।

उस समय यह माना गया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय तक पिछड़ जाएगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा आयोग और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक और निजी उद्योगों के सहयोग से धीरे-धीरे ऐसी तकनीक विकसित की, जिसने विदेशी निर्भरता को काफी हद तक समाप्त कर दिया। रिएक्टरों के डिजाइन से लेकर भारी उपकरणों, नियंत्रण प्रणालियों और सुरक्षा

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही। दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन, उन्नत उपकरणों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच लगभग बंद हो गई।

तंत्र तक भारत ने अपनी क्षमता विकसित की।

वर्ष 2008 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते ने भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान दिलाया और यूरेनियम आयात का मार्ग खोला। इससे उन परमाणु बिजलीघरों को राहत मिली जो ईंधन की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। मगर इस समझौते को एक ऐसी व्याख्या भी सामने आई, जिसमें यह मान लिया गया कि अब भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी परमाणु संयंत्रों और तकनीकों पर निर्भर होना चाहिए।

सवाल है कि किसी देश ने कठिन परिस्थितियों में विश्वस्तरीय घरेलू तकनीक विकसित कर ली हो, तो क्या उसकी प्राथमिकता उसी क्षमता का विस्तार नहीं होनी चाहिए। भारत के स्वदेशी 'प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर' आज विश्व के सबसे किफायती परमाणु संयंत्रों में गिने जाते हैं। देश 700 मेगावाट क्षमता वाले आधुनिक रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है और आगे उनकी संख्या बढ़ाने की योजना भी है।

ऊर्जा क्षेत्र में लागत का बहुत महत्व होता है। किसी परियोजना की व्यावहारिकता केवल उसकी तकनीकी श्रेष्ठता से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह कितनी किफायती है और उसके संचालन पर भविष्य में कितना व्यय होगा। यदि भारत कम लागत में

सुरक्षित और विश्वसनीय परमाणु संयंत्र बना सकता है, तो यह केवल घरेलू आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक अवसर भी है।

आने वाले वर्षों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों को स्वच्छ और निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भारत उनके लिए एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार बन सकता है।

इसी संदर्भ में हाल में तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े दस्तावेजों के कथित डेटा लीक की घटना ने एक नया सवाल खड़ा किया है। हालांकि सरकारी एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि परमाणु संयंत्र के संचालन तंत्र, रिएक्टर नियंत्रण प्रणाली या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई संवेदनशील सूचना प्रभावित नहीं हुई। फिर भी यह घटना इसका संकेत देती है कि परमाणु क्षेत्र की सुरक्षा अब केवल ऊंची दीवारों, कड़े पहर और बहुस्तरीय भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गई है।

वास्तव में, परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल स्वदेशी तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि उस तकनीक पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना भी है। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दूरसंचार की तरह परमाणु प्रौद्योगिकी भी अब भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी

है। ऐसे में यदि भारत अपनी मूलभूत ऊर्जा संरचना के लिए अत्यधिक विदेशी तकनीक या उपकरणों पर निर्भर रहता है, तो भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय तनाव का प्रभाव उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है।

भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने अपनी परमाणु क्षमता को वैज्ञानिक अनुसंधान और घरेलू औद्योगिक सहयोग के आधार पर विकसित किया है। यही कारण है कि भारतीय परमाणु संयंत्रों की निर्माण लागत विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम मानी जाती है। लागत में यह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त केवल आर्थिक लाभ नहीं देती, बल्कि भारत को वैश्विक बाजार में भी अलग पहचान प्रदान करती है।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देश स्वच्छ तथा निरंतर ऊर्जा की तलाश में हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के महंगे परमाणु संयंत्र उनके लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं हैं। भारत यदि अपनी तकनीक, निर्माण क्षमता और प्रशिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से विकसित करे, तो वह इन देशों का भरोसेमंद साझेदार बन सकता है।

भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं। यदि तीसरे चरण के परमाणु कार्यक्रम को अपेक्षित गति मिलती है, तो भारत न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिक सुरक्षित ढंग से पूरा कर

सकेगा, बल्कि भविष्य की परमाणु प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा, आधुनिक विज्ञान साझेदारी और ज्ञान-वित्तिमय से आगे बढ़ता है। इसलिए जहां नई तकनीकों, सुरक्षा मानकों और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग भारत की क्षमता को मजबूत करता हो, वहां उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

सरकार को इस दिशा में तीन स्तरों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला, स्वदेशी परमाणु उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को दीर्घकालीन वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन दिया जाए, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकें। दूसरा, परमाणु क्षेत्र की साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल संरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे कुंडनकुलम जैसी घटनाओं से मिलने वाले सबक भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकें। तीसरा, भारतीय परमाणु तकनीक को वैश्विक स्तर पर निर्यात योग्य बनाने के लिए कूटनीतिक, वित्तीय और औद्योगिक रणनीति तैयार की जाए। जिन परिस्थितियों में दुनिया ने भारत को तकनीकी रूप से अलग-थलग करने का प्रयास किया, उन्हीं परिस्थितियों में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं ने आत्मनिर्भरता की ऐसी नींव रखी, जो आज देश को सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी बन चुकी है। ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भारत के सामने चुनौती नई तकनीक खोजने की नहीं, बल्कि अपनी विकसित क्षमता पर विश्वास करने की है। परमाणु आत्मनिर्भरता की वास्तविक परीक्षा यह है कि वह अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को केवल घरेलू का विषय न बनाए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय विकास और वैश्विक नेतृत्व का आधार भी बनाए।

जर्जर सड़क और माइंस वाहनों के जाम से बेहाल जनता आप ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

भानुप्रतापपुर। अंतागढ़-नारायणपुर मुख्य मार्ग की बदहाल स्थिति और रावघाट बीएसपी माइंस प्रबंधन की कथित मनमानी को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही संस्था का अनुबंध तत्काल निरस्त करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेन्द्र नाग ने पीछव्यूडी ठेकेदार और बीएसपी माइंस प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी लापरवाही के कारण सड़क बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। उबड़-खाबड़ सड़क की वजह से 108 एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा, रोजाना हिचकोले खाते हुए स्कूल जाने वाले बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं।



20 घंटे से लगातार जाम

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि भारी ट्रकों की लगातार आवाजाही ने स्थिति भयावह हो चुकी है। कलगाँव आईटीआई के पास माइंस के भारी वाहनों के कारण लगभग 20 घंटे से भी अधिक समय से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। आम जनता को घंटों जाम में फँसना पड़ रहा है और हॉटेलों का खर्चा बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और माइंस प्रबंधन पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। युव पिंग के जिलाध्यक्ष बारसू हुंघेई ने प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अखिर कब तक क्षेत्र की जनता इस अव्यवस्था का संज्ञ लेलेगी? क्या प्रशासन किसी बड़े हथियारे का इस्तेमाल कर रहा है?

सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की बैठक संपन्न: 19 अगस्त को कांकेर में जिला स्तरीय प्रदर्शन की तैयारी



दुर्गकोंदल। दुर्गकोंदल ब्लॉक के ग्राम कोदपाखा में छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित एवं एकजुट करना रहा। इस दौरान आगामी 19 अगस्त को कांकेर जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले विशाल प्रदर्शन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज को मजबूती देने के लिए हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान समाज का सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पदाधिकारियों ने समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए तीन चरणों में आंदोलन करने की योजना सार्वजनिक की प्रथम चरण में बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन, द्वितीय चरण में संभाग स्तरीय विशाल आंदोलन, तृतीय चरण में

प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन। जनसंपर्क और शत-प्रतिशत सहभागिता का आह्वान: बैठक में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और हर गांव में जनसंपर्क अभियान चलाना अनिवार्य है। इसके लिए घर-घर जाकर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आंदोलन में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों—सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। संगठित समाज ही मजबूत समाज होता है। आइए, अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई के लिए 19 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में कांकेर पहुंचकर इतिहास रचें। इस बैठक में सुकाल राम, मनु यादव, सत्तु राम यादव, अशोक यादव, लखन लाल सिन्हा, रमेश सिन्हा, नागेश पाण्डे, शिव प्रसाद दिवान, विष्णु प्रसाद पटेल, हेरेश चक्रधारी, यशवंत चक्रधारी उपस्थित रहे।

ज्ञानेश्वरी यादव ने बढ़ाया प्रदेश का मान: भाजयुमो

जिला अध्यक्ष नागेश देवांगन ने कहा दृढ़ इच्छाशक्ति, कठोर परिश्रम और अनुशासन के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता



कोडगांव। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नागेश देवांगन ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमण्डल खेल-2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाली राजनादगाँव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई देते हुए कहा है कि यह सम्मान प्रदेश की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प का सम्मान है। नागेश देवांगन ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने पहले ही राष्ट्रमण्डल खेलों में रजत पदक जीतकर यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, कठोर परिश्रम और अनुशासन के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। भाजयुमो जिला अध्यक्ष नागेश देवांगन ने कहा कि

महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ज्ञानेश्वरी ने न केवल देश के लिए पदक जीता, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। यह उपलब्धि प्रदेश के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगी। नागेश देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व वाली भाजपा की राज्य सरकार प्रदेश की युवाओं को हरसम्भव मदद पहुंचा रही है। प्रदेश के

युवा खेल के साथ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने ज्ञानेश्वरी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उन्हें 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा आउट ऑफर्टन डीएसपी पद पर पदोन्नति देने की घोषणा की। इससे प्रदेश के युवाओं में रुचि बढ़ेगी। नागेश देवांगन ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता हासिल की है। उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मॉजिल दूर नहीं रहती। राज्य सरकार ने उन्हें आउट ऑफर्टन डीएसपी पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी उपलब्धि का सम्मान हो और प्रदेश के अन्य खिलाड़ी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित हों। भाजयुमो जिला अध्यक्ष नागेश देवांगन ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का पूरा अवसर दे रही है जिससे महिलाएँ को हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के अधिक-से-अधिक खिलाड़ी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा लहराएँ तथा देश और प्रदेश का नाम विश्वभर में रोशन करें। ज्ञानेश्वरी यादव जैसी खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ इस दिशा में नई पीढ़ी का आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करेंगी। नागेश देवांगन ने विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत और छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मंच पर नई ऊँचाइयों तक पहुंचाएंगी। प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें अवसर देना और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना सरकार की खेल नीति का महत्वपूर्ण आधार है। यही प्रयास आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को खेलों के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा।

आम आदमी पार्टी और स्थानीय ग्रामीणों की मुख्य मांगें

अंतागढ़-नारायणपुर मार्ग का तत्काल डबलरीकरण/मरम्मत कार्य शुरू किया जाए। सड़क निर्माण पूरा होने तक माइंस के भारी ट्रकों की आवाजाही पर तुरंत रोक लगाई जाए।

उग्र आंदोलन की चेतावनी

आप के कांकेर जिला महासचिव शिव पेटाई ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं करवाई और भारी वाहनों के परित्यक्त पर रोक नहीं लगाई, तो पार्टी स्थानीय ग्रामीणों को साथ लेकर सड़कों पर उग्र उग्र उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन-प्रशासन की होगी।

पूर्व घोर नक्सल प्रभावित पीड़ियाकोट में पहली बार हुआ संस्थागत प्रसव

मायका सेंटर डुंगा में दो महिलाओं ने सुरक्षित रूप से बच्चों को दिया जन्म, जच्चा-बच्चा सभी स्वस्थ

नारायणपुर। अनुसूमाड़ के दुर्गम एवं पूर्व में घोर नक्सल प्रभावित रहे ग्राम पीड़ियाकोट में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। गांव में पहली बार दो गर्भवती महिलाओं का सफलतापूर्वक संस्थागत प्रसव कराया गया। यह उपलब्धि दुर्गम क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम पीड़ियाकोट निवासी दशरी, पति बुधराम, आयु 38 वर्ष एवं सुधरी, पति मुरा, आयु 35 वर्ष को स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा सुरक्षित मातृत्व एवं संस्थागत प्रसव के संबंध में निरंतर परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दोनों महिलाओं एवं उनके परिवारों को संस्थागत प्रसव के महत्व तथा मायका सेंटर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी गई। काउंसलिंग के पश्चात दोनों गर्भवती महिलाओं को दुर्गम मार्गों से बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से मायका सेंटर डुंगा पहुंचाया गया। मायका सेंटर में दोनों महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच,



आवश्यक देखभाल एवं सतत निगरानी की गई। 26 जुलाई को दशरी ने 2.480 किलोग्राम वजन के एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, जबकि सुधरी ने 2.400 किलोग्राम वजन की एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। वर्तमान में दोनों माताएं एवं दोनों नवजात स्वस्थ हैं तथा स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच एवं देखभाल की जा रही है। पूर्व में घोर नक्सल प्रभावित रहे

पीड़ियाकोट जैसे दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच सीमित रहने के कारण गर्भवती महिलाओं के लिए समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य अमले की सतत काउंसलिंग, नियमित संपर्क एवं बाइक एम्बुलेंस की सुविधा ने दोनों गर्भवती महिलाओं को समय रहते स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मायका सेंटर की पहल से दुर्गम क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल, सुरक्षित उद्धार, नियमित स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव तथा प्रसव उपरांत आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पीड़ियाकोट में पहली बार संस्थागत प्रसव का सफलतापूर्वक होना स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच और समुदाय में संस्थागत प्रसव के प्रति बढ़ते विश्वास का सशक्त उदाहरण है।

मूर्तिकला एवं टेराकोटा शिल्पकार परमेश्वर चक्रधारी ‘कला गुरु सम्मान 2026’ से सम्मानित

भानुप्रतापपुर। संस्कार भारती इकाई कांकेर द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कला के देवता भगवान नटराज और मां सरस्वती के पूजन-अर्चन के साथ ‘कला गुरु सम्मान’ समारोह अत्यंत गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। मांझा पारा स्थित श्री सत्य साईं भवन में आयोजित इस समारोह में क्षेत्र के प्रसिद्ध मूर्तिकला व टेराकोटा शिल्पकार परमेश्वर चक्रधारी को ‘कला गुरु सम्मान 2026’ से नवाजा गया।



संदर्भ, साधना और उपलब्धियों की यात्रा: कांकेर जिले के ग्राम बांसला ब्लॉक भानुप्रतापपुर के निवासी परमेश्वर चक्रधारी बीते डेढ़ दशक से अधिक समय से मूर्तिकला एवं टेराकोटा शिल्प के क्षेत्र में अपनी अनूठी कला साधना में लीन हैं। शिक्षण-प्रशिक्षण और कठिन संघर्षों से होकर गुजरी उनकी यह कला कई राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त कर चुकी है और वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के सम्मान के लिए नामांकित हुई है। परमेश्वर ने अपनी इस मूर्ति की सौधी सुगंध को न केवल जीवंत रखा है, बल्कि कला की परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं। समारोह के दौरान भावुक होते हुए उन्होंने साझा किया कि उनकी धर्मपत्नी व शिष्या बसंती चक्रधारी द्वारा माटी से गढ़ी गई ‘आदिवासी

घोटुल’ कलाकृति को भी राज्य स्तरीय सम्मान के लिए नामांकित किया गया है। भव्य सम्मान एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां: समारोह में रामशरण जैन द्वारा परमेश्वर का तिलक-चंदन लगाकर वंदन किया गया। तत्पश्चात संस्थ द्वारा शॉल, श्रीफल, मोमेंटो, सम्मान पत्रक एवं नाद राशि भेंट कर उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी बसंती चक्रधारी का भी शॉल एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना6 और दीप प्रज्वलन के साथ

हुआ। मंच संचालन कर रहे प्रांत मंत्री रिजेंद्र गंजी ने अपनी स्पर्चित पक्तियों से वातावरण को संगीतमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान सत्य साईं बाबा समिति की भजन मंडली ने भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। 100 से अधिक लोगों को दे चुके हैं प्रशिक्षण: उल्लेखनीय है कि परमेश्वर चक्रधारी ने माटी कला बोर्ड, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, जिला पंचायत और छात्र फाउंडेशन हैदराबाद के सहयोग से अब तक 100 से भी अधिक लोगों को शिल्प कला का निःशुल्क व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया

एनएमडीसी अधिकारी मोहित तोमर ने 47वीं बार रक्तदान कर बचाई ब्रजुर्ग की जान

किरंदुल। नर सेवा ही नारायण सेवा को साकार करते हुए एनएमडीसी बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स के अधिकारी मोहित तोमर ने 5 अगस्त को 47वीं बार स्वीच्छक रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। उनका यह दान ओ-निगेटिव दुर्लभ रक्त समूह का था, जो किरंदुल प्रोजेक्ट हॉस्पिटल में एक मरीज के ऑपरेशन के आपातकालीन समय में काम आया।



10 किमी का सफर तय कर पहुंचे मदद को: बचेली के डिर्वांजिट 10/11/ए स्क्रीन-प्लांट में उप प्रबंधक यात्रिकी के पद पर कार्यरत तोमर द्यूटी के लिए निकल ही रहे थे कि उन्हें एक फोन आया। फोन करने वाले युवक ने बताया कि उसकी मां का ऑपरेशन होना है और ओ-निगेटिव रक्त की तत्काल जरूरत है। दुर्लभ रक्त समूह की बात सुनते ही तोमर ने बिना समय गंवाए अपनी धर्मपत्नी के साथ बचेली से लगभग 10

किलोमीटर का सफर तय कर किरंदुल हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों से परामर्श और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तोमर ने बिना समय गंवाए अपनी मिल जाने से मरीज के परिजनों ने राहत

की सांस ली। ईश्वर ने बड़ा काम करवाया: रक्तदान के बाद तोमर ने कहा, आज का दिन आत्मसंतुष्टि से भरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि माताजी शीघ्र स्वस्थ हों। भगवान भुखे संवल दे ताकि मैं आगे भी निस्वार्थ भाव से रक्तदान की सेवा जारी रख सकूँ। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार नियमित रक्तदान से न केवल जरूरतमंदों को जीवनदान मिलता है, बल्कि दाता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। इससे हृदय रोग का खतरा कम होता है और शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्थानीय निवासियों, सहकर्मियों और अस्पताल प्रशासन ने तोमर के इस त्याग की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

पटेलपारा में सीसी सड़क निर्माण का भूमिपूजन नपा अध्यक्ष रूबी सिंह ने किया, वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

किरंदुल। नगर पालिका परिषद किरंदुल के वार्ड क्रमांक 18 पटेलपारा में सीसी सड़क निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह के करकमलों द्वारा किया गया। यह सीसी सड़क मुख्य मार्ग से लक्ष्मण के घर तक निर्मित की जाएगी। सड़क निर्माण की मांग वार्डवासियों द्वारा कई वर्षों से की जा रही थी। निर्माण से क्षेत्र में आवागमन बेहतर होगा और बरसात में कीचड़ व जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। नपा अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि नगर के सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। जगहगत से जुड़े विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। वार्डवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूर्ण कर समाज विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। वार्ड पार्श्व अनिल



मरकाम ने कहा कि अध्यक्ष के सहयोग से यह मांग पूरी होने जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और वार्ड के विकास को नई गति मिलेगी। पार्श्व लक्ष्मी ठाकुर, यशोव चुवम, बी. रूप

रानी, थामस बाबू दुर्गम, इला पटेल, एलडमेन सुनीता साहू, पूर्व नपा अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह, ए.एम.एन.एस. के डॉ. तेज प्रकाश, उप अभियंता संजय मार्कण्डेय एवं वार्डवासी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने जिला स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वयन समिति की बैठक में की समीक्षा

जन्म-मृत्यु पंजीयन को समयबद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए निर्देश

कोण्डगांव। कलेक्ट्रेट सभागाय कोण्डगांव में जन्म-मृत्यु पंजीयन व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर नूपुर राशि पद्म की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध पंजीयन और प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों में जन्म एवं मृत्यु का निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन सुनिश्चित



करते हुए हितग्राहियों को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएँ। समीक्षा के दौरान जिला अस्पताल कोडगांव में समय पर जन्म-मृत्यु पंजीयन नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन एवं अधीक्षक जिला अस्पताल से स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही विलंबित पंजीयन के मामलों में

सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदारों को नियमानुसार कार्रवाई करने तथा फर्जी पंजीकरण एवं युजर आईडी/पासवर्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन

अधिकारियों को वर्ष 2008 के बाद के जन्म-मृत्यु पंजीयन से संबंधित अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन के लिए जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि अभिलेखों का सुव्यवस्थित डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

संक्षिप्त समाचार

आईटीआई की परीक्षाएं 17

अगस्त से, आवेदन 7 अगस्त तक

बिलासपुर। राज्य व्यावसायिक परीक्षा (एससीवीटी) एवं हायर सेकण्डरी व आईटीआई की संयुक्त अध्यापन योजना में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की आईटीआई ट्रेड की परीक्षा (पुरानी प्रणाली एवं नई परीक्षा प्रणाली) माह अप्रैल 2026 की प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षाएं 17 अगस्त 2026 से 24 अगस्त 2026 तक सम्पन्न होनी है। परीक्षा हेतु प्रवेश सत्र 2025–2026 में प्रवेशित एकवर्षीय व्यवसाय, सत्र 2025–2027 में प्रवेशित द्विवर्षीय व्यवसाय के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2024–2026 में प्रवेशित द्विवर्षीय व्यवसाय के द्वितीय वर्ष के नियमित पात्र प्रशिक्षणार्थी एवं सत्र 2023–2025 में प्रवेशित द्विवर्षीय व्यवसाय के द्वितीय वर्ष, सत्र 2024–2026 में प्रवेशित द्विवर्षीय व्यवसाय के प्रथम वर्ष, सत्र 2024–2025 में प्रवेशित एकवर्षीय व छः माह व्यवसाय के पूरक पात्र प्रशिक्षणार्थी जिनके प्रयास शेष हैं तथा सत्र 2023–2024 के छः माह व्यवसाय एवं सत्र 2022–2024 के द्विवर्षीय व्यवसाय के पूरक पात्र प्रशिक्षणार्थी जिनके प्रयास शेष हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 तक है।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु नामांकन आमंत्रित

बिलासपुर। भारत सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2027 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किये गये है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2026 तक है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता, मापदंड तथा नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित पोर्टल अवाइर्स डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। चयन के उपरांत पुरस्कार की घोषणा नेताजी की जयंती 23 जनवरी 2027 को की जाएगी।

पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला: सूरजपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

सूरजपुर। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में थाना प्रेमनगर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त लाठी भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार, ग्राम गौरीपुर निवासी मटुकधारी यादव ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जुलाई 2026 की रात करीब 10 बजे ग्राम कंचनपुर निवासी रविन्द्र रजक पेट्रोल पंप से उधारी में लिए गए पेट्रोल के पैसे लेने उसके दुकान पर आया था। उसी दौरान लक्ष्मण, संदीप, जमुना और कमलेश लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद करते हुए रविन्द्र रजक पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल रविन्द्र रजक को पहले प्रेमनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रार्थी की शिकायत पर थाना प्रेमनगर में अपराध क्रमांक 87/2026 के तहत धारा 109(1), 296, 351(3), 115(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर थाना प्रेमनगर पुलिस ने विवेचना के दौरान दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पृष्ठताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी भी जब्त कर ली गई। गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मण यादव (40 वर्ष), निवासी गौरीपुर यादवपारा, थाना प्रेमनगर संदीप यादव (24 वर्ष), निवासी गौरीपुर यादवपारा, थाना प्रेमनगर जमुना प्रसाद यादव (55 वर्ष), निवासी गौरीपुर यादवपारा, थाना प्रेमनगर कमलेश यादव (20 वर्ष), निवासी गौरीपुर यादवपारा, थाना प्रेमनगर इस कार्रवाई में एएसआई गुड्डू कुशवाहा, प्रधान आरक्षक प्रमोद लकड़ु, आरक्षक दीपक यादव, वृजेश काशी एवं हरिशचंद्र दास की सराहनीय भूमिका रही।

पीपल चौक पर सूखा डंगाल बन सकता है हादसे का कारण, स्थानीय लोगों ने हटाने की उठाई मांग

रामानुजगंज। नगर के सबसे व्यस्त एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्र पीपल चौक में स्थित पीपल के पेड़ का एक सूखा डंगाल बाजार की ओर झुक गया है, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। पूरे दिन लोगों की आवाजाही रहने तथा आसपास दुकानें होने के कारण स्थानीय नागरिकों में चिंता का माहौल है। स्थानीय नागरिक कांग्रेस नेता अजय सोनी, संजय गुप्ता, शक्ति सोनी, अजय गुप्ता गुड्डू सहित अन्य लोगों ने नगर पालिका से मांग की है कि संभावित दुर्घटना को देखते हुए सूखे डंगाल को तत्काल कटवाया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते इसे नहीं हटया गया तो तेज हवा या बारिश के दौरान यह गिरकर किसी बड़ी जहाजिन या संपत्ति के नुकसान का कारण बन सकता है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे तथा सूखे डंगाल को शीघ्र कटवाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

जिले के किसान अब 14 अगस्त तक... करा सकेंगे उद्यानिकी फसलों का बीमा

बिलासपुर। उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद के लिये खरीफ वर्ष 2026–27 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा संचालित की जा रही है। उप संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के इच्छुक ऋणी एवं अग्रणी कृषक 31 जुलाई 2026 तक निकटतम लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं बीमा कंपनी के

प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। इस हेतु बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री थानेश्वर साहू मो0न0 99071–22727, तखतपुर के उद्यान विकास अधिकारी श्री जैनेन्द्र कुमार पैकरा 6265981957, कोटा के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री रामनाथ सिंह नेताम 7828815637, मस्तूरी की प्रभारी उद्यान अधीक्षक श्रीमती निशा चंदेल 7000441324 एवं बिल्हा के प्रभारी उद्यान अधीक्षक श्री राकेश कुमार सेन्डे 7000181970 से संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है। चर्यनित उद्यानिकी फसलों खरीफ के लिए किसानों द्वारा द्रैय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। बिलासपुर जिले में खरीफ मौसम के फसलों हेतु 200 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। टमाटर फसल के लिए



प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए एवं किसान देय प्रीमियम राशि 6 हजार, बैंगन के लिए बीमित राशि 77 हजार रुपए एवं प्रीमियम राशि 3 हजार 850 रुपए, मिर्च के बीमित राशि 68 हजार रुपए एवं

प्रीमियम राशि 3 हजार 400 रुपए, अदरक के लिए बीमित राशि 1 लाख 50 हजार रुपए एवं प्रीमियम 7500 रुपए, केला के लिए बीमित राशि 85 हजार एवं प्रीमियम राशि 4 हजार 250, पपीता के लिए बीमित राशि 87 हजार एवं प्रीमियम राशि 4 हजार 350 और अमरूद के लिए बीमित राशि 45 हजार एवं प्रीमियम राशि 2 हजार 250 रुपए निर्धारित है। किसानों के हानि का मूल्यांकन अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित स्वचलित मौसम केंद्र से प्राप्त 4 आवरित जोखिमों जैसे कम या अधिक तापमान, कम या अधिक या बेमौसम वर्षा, वायु गति, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम के प्रमाणित आंकड़ों एवं अधिसूचित टर्मशीट के अनुसार दावा गणना की जाएगी। दावा राशि का भुगतान सीधे

किसानों के खाते में किया जाएगा। खरीफ मौसम के टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक फसल हेतु ओलावृष्टि हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं. 18004190344 पर तथा टोटल शिकायत निवारण पोर्टल या लिखित रुप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व एवं संबंधित क्षेत्र के उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यूरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करना होगा। संबंधित संस्था/विभाग 48 घंटा के भीतर कृषकों से प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यूरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित) बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है।

सिम्स में पहली बार 78 वर्षीय महिला मरीज के अंडाशय कैंसर ट्यूमर की सफल सर्जरी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आर्युर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने एक अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कैंसर शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक संपन्न कर 78 वर्षीय महिला मरीज को नया जीवन प्रदान किया। मरीज, निवासी दर्राघाट, बिलासपुर, पिछले 5–6 महीनों से पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द तथा पेट में तेजी से बढ़ रही विशाल गांठ से पीड़ित थीं। लगातार परेशानी के कारण मरीज पहले निजी अस्पताल पहुंचीं, जहां जांच के बाद ऑपरेशन एवं उपचार पर लगभग 2 से 3 लाख रुपये तक का खर्च बताया गया। आर्थिक स्थिति के कारण परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद मरीज को सिम्स, बिलासपुर लाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के उपरांत आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका संपूर्ण उपचार एवं ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। विस्तृत जांच के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि मरीज रजोनिवृत्ति के बाद की अवस्था में थीं तथा उनके बाएं अंडाशय में लगभग 15x12x10 सेंटीमीटर आकार एवं

लगभग 1 किलोग्राम वजन का कैंसरयुक्त ट्यूमर विकसित हो चुका था। ट्यूमर के बड़े आकार के कारण आसपास के महत्वपूर्ण अंगों पर दबाव पड़ रहा था। इसकी जानकारी रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह द्वारा सोनोग्राफी जांच के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि शल्य चिकित्सा अत्यंत जटिल एवं उच्च जोखिम वाली होगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहुविषयक टीम द्वारा मरीज का समुचित मूल्यांकन कर 03 अगस्त 2026 को कैंसर की चरण निर्धारण शल्य चिकित्सा, ट्यूमर भार कम करने की शल्य चिकित्सा, गर्भाशय एवं दोनों अंडाशयों को निकालने की शल्य चिकित्सा, बाई मूत्रवाहिनी की मरम्मत तथा बाई मूत्रवाहिनी में डबल-जे स्टेंट प्रत्यारोपण जैसी जटिल शल्य प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न की गईं। इस सफल ऑपरेशन में गायनेकोलॉजिकल सर्जरी टीम के डॉ. संगीता रमन दोगी (विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर), डॉ. दीपिका, डॉ. सौम्या एवं डॉ. वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनरल सर्जरी विभाग से डॉ.



रघुराज सिंह (प्रोफेसर), डॉ. बी. डी. तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं डॉ. गरिमा ने सहयोग प्रदान किया। वहीं एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. बी. रायजादा, डॉ. एस. कुजूर एवं डॉ. एम. देववर्मा ने शल्य चिकित्सा को सुरक्षित एवं सफल बनाने में महत्वपूर्ण

योगदान दिया। सिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने बताया कि इतने बड़े अंडाशय ट्यूमर की शल्य चिकित्सा के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव तथा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं आंत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचने की संभावना बनी रहती है। ऐसे मामलों में

सड़क सुरक्षा के लिए रायगढ़ ट्रैफिक पुलिस का अभिनव अभियान शुरू

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में एक अभिनव सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी एवं एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) श्री पुष्पेन्द्र बघेल के मार्गदर्शन तथा ट्रैफिक डीएसपी श्री उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीमों द्वारा मुख्य मार्गों पर सड़क किनारे स्थित वृक्षों पर झलदृढ़ स्क्रूहृदृढ़ रेडियम रिफ्लेक्टर स्टीकर लगाए जा रहे हैं। अक्सर रात्रि के समय सड़क किनारे खड़े पेड़ अंधेरे में स्पष्ट दिखाई नहीं देते, जिससे तेज रफ्तार या विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों के चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसी जोखिम

को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने जिले के विभिन्न मार्गों का सर्वे कर ऐसे चिन्हित वृक्षों पर उच्च गुणवत्ता वाले रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जो वाहन की हेडलाइट पड़ते ही दूर से चमकते हैं और चालक को पहले से सतर्क कर देते हैं। यह छोटा लेकिन प्रभावी प्रयास विशेष रूप से रात के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान के लिए थाना यातायात की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो जिले के विभिन्न मार्गों पर लगातार कार्य कर रही हैं। अभियान के तहत कट उर्दना-गेरवानी-लाखा मार्ग, पहाड़ मंदिर-बनोरा मार्ग तथा इंदिरा विहार-हमीरपुर मार्ग में सड़क किनारे चिन्हित पेड़ों पर झलदृढ़ स्क्रूहृदृढ़ रेडियम रिफ्लेक्टर स्टीकर लगाए

गए। आगामी दिनों में जिले के अन्य संवेदनशील एवं दुर्घटना संभावित मार्गों पर भी यह कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे रात्रि में निर्धारित गति सीमा का पालन करें, हाई बीम का अनावश्यक उपयोग न करें, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सड़क संकेतकों एवं रिफ्लेक्टर मार्किंग का सम्मान करते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस केवल प्रवर्तन ही नहीं, बल्कि ऐसे नवाचार भी कर रही है जो सीधे लोगों की सुरक्षा से जुड़े हैं।

आवास मित्र ने रखा विकल्प जांच टीम ने शिकायत को पाया सही.....

कोरबा। भारत सरकार की प्लैंगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में कई जगह मनमानी हो रही है। निगरानी के लिए रखा गया मैदानी अमला अपने हिसाब से काम कर रहा है। करतला ब्लॉक के कथरीमाल में जनपद पंचायत ने जिस आवास मित्र को काम पर रखा है उसने अपने एवज में दूसरे की सेवा शुरू कर दी। दो सदस्यीय जांच टीम ने इस शिकायत को सही पाया। सूत्रों के अनुसार पीएम आवास योजना में अधूरे आवासों की जाीयो टैगिंग कर इसे पूरा बनाने का काम चल रहा है। यहां पर कामज में नियुक्ति किसी और की की गई है लेकिन फ़ैल्ड में काम कोई और कर रहा है। इस बारे में स्थानीय लोगों की ओर से प्रशासन को शिकायत

की गई। अधिकारियों ने संज्ञान लेने के साथ करारोपण अधिकारी कंवर और तकनीकी सहायक प्रफुल्ल दीक्षित को जांच के लिए भेजा। उन्होंने मौके पर भीतिक सत्यापन किया और शिकायत को सही पाया। मालूम चला कि जिसकी नियुक्ति जनपद ने आवास मित्र के तौर पर नहीं की वह अवैध रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। इस पंचायत में पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन से लेकर संबंधित प्रक्रियाओं की पूर्ति में नियम-पालन पर कई सवाल खड़े हुए हैं। जांच टीम ने कुछ लोगों से पृष्ठताछ की तो सभी ने यही बताया कि आवास मित्र के तौर पर जिसे नियुक्त किया गया, वह दूसरे काम कर रहा है। वह चाहता है कि आवास मित्र के रूप में सरकार से मानदेय

घर में चोरी का 24 घंटे में खुलासा,चांदी के जेवर और मोबाइल सहित आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। रायगढ़ जिले की भूपदेवपुर पुलिस ने घर में चोरी के मामले का त्वरित खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गए चांदी के पायल, बिछिया और क़ष्ठह कंपनी का मोबाइल फोन सहित करीब 30 हजार रुपये का पूरा चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया है। पृष्ठताछ के दौरान आरोपी ने एक बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की वारदात भी स्वीकार की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव के मार्गदर्शन में संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, ग्राम डोंगाढकेल निवासी घनश्याम साहू ने 4 अगस्त को थाना भूपदेवपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3–4 अगस्त की रात अज्ञात चोर उसके घर में घुसकर आलमारी से एक जोड़ी चांदी के पायल (करीब 20 हजार रुपये), एक जोड़ी चांदी की बिछिया (करीब 1 हजार रुपये) और लगभग 9 हजार रुपये कीमत

का क़ष्ठह मोबाइल चोरी कर ले गया। सुबह पड़ोसी ने सूचना दी कि घर का पर्स, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और स्कूल बैग आंगन में पड़े हैं। वहीं गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने सनत कुमार उर्फ नानू साहू को सामान फेंकते हुए देखा था। शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 112/2026 के तहत बीएनएस की धारा 331(4) एवं 305(ए) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी रोशन कुमार कौशिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश गांव की। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी गांव छोड़कर अपने परिचित के यहां छिपा हुआ था, लेकिन मुखबिर् की सूचना पर गांव लौटते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पृष्ठताछ में आरोपी ने बताया कि उसने रात करीब 2 बजे घर के मुख्य गेट से प्रवेश कर आलमारी से जेवर और मोबाइल चोरी किया तथा पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया। पृष्ठताछ के दौरान आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने 4–5 जुलाई 2026 की रात जिला

सक्की के थाना चंद्रपुर क्षेत्र स्थित एक मेडिकल स्टोर के सामने से बुलेट क्लासिक-350 (छत 13 ड़र 4096) भी चोरी की थी। उसने मोटरसाइकिल को ग्राम बरक्षगुड़ा के पास मांड नदी किनारे झाड़ियों में छिपाने की बात बताई। पुलिस के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल पहले ही थाना चंद्रपुर पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है। सनत कुमार उर्फ नानू साहू (29 वर्ष), निवासी ग्राम डोंगाढकेल, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि संपत्ति संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई और चोरी गए सामान की शीघ्र बरामदगी रायगढ़ पुलिस की प्रार्थामिकता है। उन्होंने आमजन से किसी भी सौंदग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रोशन कुमार कौशिक, प्रधान आरक्षक संजय भूषण तिकौं तथा आरक्षक हरिशंकर नायक, प्रदीप तिवारी और संतोष जायसवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

तेज रफ्तार बाइक ने शिक्षक को मारी टक्कर इलाज के दौरान मौत



■ बताया जा रहा है कि सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक ने शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कटघोरा थाना क्षेत्र में पत्नी को स्कूल छोड़कर लौट रहे एक शिक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे में बाइक सवार युवक भी घायल हुआ है, जबकि बाइक पर पीछे बैठा दूसरा युवक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक, मृतक शिक्षक अजय थवाईत और उनकी पत्नी मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक, मृतक शिक्षक अजय थवाईत और उनकी पत्नी मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक, मृतक शिक्षक अजय थवाईत रोज की तरह अपनी पत्नी को एक्टिवा से स्कूल छोड़ने पहुंचे थे। पत्नी को स्कूल गेट पर छोड़ने के बाद शिक्षक पैदल सड़क पार कर रहे

थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिक्षक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल शिक्षक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि, गंभीर चोटों के कारण डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस सड़क हादसे में बाइक चला रहा युवक भी घायल हुआ है। उसे कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं बाइक पर पीछे बैठा दूसरा युवक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार युवक की तलाश में जुटी है। हादसे की वार्ताविक परिस्थितियों और बाइक सवारों की भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक शिक्षक के शव का पोस्टमॉरम कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटनाकारित बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फारर युवक की पहचान और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

निगम की उदासीनता बरकरार : बिना क्लोरीन का पानी शहर में हो रहा सप्लाई, 9 मोटर पंप भी बंद

ननि नेता प्रतिपक्ष से साथी पार्षदों के साथ वॉटर फिल्टर प्लांट का किया निरीक्षण

राजनंदागांव। शहर में गंदे पानी की सलाई हो रही है, लोगों की सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। इसे देखते हुए कांग्रेसी पार्षदों ने मोहारा वॉटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। यहां से बिना क्लोरीन का पानी सप्लाई किया जा रहा है। प्लांट में 18 में से 09 पंप बंद पड़े हैं। यह पहली मर्तबा नहीं है, जब मोहारा प्लांट को लेकर खामियां सामने आ रही है। लेकिन नगर निगम प्रशासन इस पर खामोशी ही बैठा हुआ है। उसकी यह उदासीनता समझ से परे है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने नगर निगम प्रशासन, महापौर मधुसूदन यादव और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।



पिल्ले ने आरोप लगाया कि शहर की जनता पिछले कई दिनों से बिना क्लोरीन वाला पानी पीने को मजबूर है जबकि जल संयंत्र में कई गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक खामियां बनी हुई हैं। नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवाल को बीच

नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले को उनकी ही पार्टी के पार्षद एवं जल विभाग के पूर्व सभापति सतीश मसीह ने मोहारा जल संयंत्र की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद संतोष पिल्ले सीधे जल संयंत्र पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

फिटकरी की मात्रा भी कम, ये सेहत से खिलवाड़

निरीक्षण के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जल संयंत्र में पिछले 10 दिनों से क्लोरीन गैस की आपूर्ति बंद है जिससे शहरवासियों को बिना क्लोरीन वाला पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्लोरीन की जगह केवल ब्लोचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा है जो पर्याप्त नहीं है। साथ ही फिटकरी की मात्रा भी बेहद कम है और संयंत्र में केवल पांच दिनों का ही फिटकरी का स्टॉक बचा है। पिल्ले ने कहा कि जल संयंत्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 18 मोटर पंपों में से 9 पंप बंद पड़े हैं जिससे जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दो नए पंप बिना विधिवत टेंडर प्रक्रिया के लगाए गए हैं जिसकी जांच होनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने सांसद, विधायक और महापौर पर साधा निशाना

नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि निगम प्रशासन पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है और महापौर मधुसूदन यादव इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जल टंकियों की सफाई की तिथि भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की जा रही है जिससे लोगों में और अधिक चिंता बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक डॉ. रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाते हुए पिल्ले ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि फिटकरी रायपुर, नागपुर और महाराष्ट्र से मंगाई जा रही है। यदि समय पर इसकी आपूर्ति नहीं हुई तो जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक संकट में आ सकती है। उन्होंने भाजपा की टिपल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद, विधायक और महापौर सभी भाजपा के हैं फिर भी शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

आईआईटी भिलाई के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट पीईटी प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य एवं भविष्य की प्रिंटिंग के लिए संभावित सामग्री में बदला

दुर्ग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के शोधकर्ताओं ने पीईटी प्लास्टिक कचरा को एक उच्च-मूल्य वाली पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करने की एक अभिनव तकनीक विकसित की है। इस नई सामग्री को बार-बार नया आकार दी जा सकती है, भरमत्त की जा सकती है तथा पुनर्चक्रित की जा सकती है। यह उपलब्धि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, सतत विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शोध आईआईटी भिलाई के रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. संजीव बनर्जी के नेतृत्व में प्रियंक सिन्हा, भरतभूषण मेथाम एवं ओंकारनाथ वर्मा द्वारा किया गया। इस शोध के निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं, जो टिकाऊ



सामग्री के क्षेत्र में आईआईटी भिलाई के बढ़ते योगदान को दर्शाते हैं। इस विकसित तकनीक के लिए शोधकर्ताओं ने भारतीय पेटेंट आवेदन भी दाख किया है। बोतलें विश्वभर में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों में शामिल हैं, विशेषकर पेय पदार्थों की बोतलों और खाद्य पैकेजिंग में। इनसे प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। यद्यपि इनका पुनर्चक्रण किया जाता है, लेकिन पारंपरिक पुनर्चक्रण

तकनीकों में प्लास्टिक की गुणवत्ता धीरे-धीरे कम होती जाती है, जिससे इसका दोबारा उपयोग सीमित हो जाता है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए आईआईटी भिलाई की शोध टीम ने सबसे पहले नीलगिरी की पत्तियों से एक हर्बिट, पुनः उपयोग योग्य उत्प्रेरक विकसित किया। यह उत्प्रेरक अपशिष्ट बोतलों को एक मूल्यवान रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक में परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक को चुंबक की सहायता से आसानी से अलग कर पुनः कई बार

उपयोग किया जा सकता है, जिससे पुनर्चक्रण प्रक्रिया अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और किफायती बनती है। इसके बाद इस रासायनिक निर्माण खंड को एक उच्च-प्रदर्शन, पुनः संसाधित एवं संभावित 3D प्रिंट योग्य गतिशील पॉलिमर में परिवर्तित किया जाता है। यह तकनीक फेंकी गई बोतलों को पर्यावरणीय बोझ से मूल्यवान इंजीनियरिंग सामग्री में बदलकर वेस्ट-टू-वैल्यू की अवधारणा को साकार करती है।

देर रात तक लोगों ने रफी के गीतों का आनंद लिया



कुम्हारी। भारतीय सिने जगत में संगीत और गीत में अपने मधुर आवाज से लोगों को अपना देवाना बनाने वाले संगीत जगत के अमर गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया इस वर्ष यह आयोजन स्थानीय कलाकारों के कराओके म्यूजिकल रूप के साथ मिलकर मो. रफी को उनके गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए इस बार इस आयोजन को ग्रीन पार्क में रखा गया था। आयोजन में अतिथि के रूप में नगरपालिका परिषद कुम्हारी की अध्यक्ष मीना वर्मा उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह राजनूप

समाजसेवी ललित अग्रवाल (रायपुर) एवं पत्रकार ललित साहू (दुर्ग) उपस्थित थे। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने मो. रफी के चित्र पर मात्कारण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की कार्यक्रम की शुरुआत मो. रफी के अमर गीत तुम मुझे यूँ धुला न पाओगे धीम सांग से हुई जिसे किसान राठौड़ ने अपने सुमधुर स्वर में गाकर संगीत यात्रा का शुभारम्भ किया। इसके पश्चात नगर के प्रतिभाशाली गायकों ने जिनमे डॉ. अविनाश गुप्ता, रामकुमार सोनी, अशोक राठौ, अर्नब सूर, प्रकाश गज्जर, अंजना सिंह, अवधेश शुक्ला, संजय श्रीवास्तव, के. रवि, धर्मेन्द्र राव, के. प्रकाश, संतोष सोनी, राजेश निषाद, मो. रऊफ

जितेंद्र कुशवाहा, शैलेन्द्र खरे एवं रविन्द्र कुमार थापा ने अपने गायन कौशल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में रायपुर से पधारि समाजसेवी ललित अग्रवाल ने अपनी उमदा प्रस्तुति से श्रोताओं की भरपूर तालियां बटोरीं। देर रात तक चले इस सुरीले संगीत का आनंद लेते हुए बड़ी संख्या में श्रोताओं ने अपनी उपस्थिति दी। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब अध्यक्ष विक्रम शाह ठकुर ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संगीतमय आयोजन में रायपुर, दुर्ग और भिलाई के पत्रकार भी उपस्थित रहे।

पावर हाउस सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग के खिलाफ निगम की कार्रवाई, वाहन किए गए जब्त

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम के जोन 3 राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा पावर हाउस सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफकार्रवाई की गई। पावर हाउस सर्विस रोड पर सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े किए जाने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा था। इसके साथ ही सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग के कारण यातायात बाधित होने तथा दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। नागरिकों की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सड़क पर अवैध रूप से



खड़े वाहनों को जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों को पुलिस प्रशासन के सहयोग से थाना छवनी पहुंचाया गया। निगम प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक सड़कों, सर्विस रोड एवं यातायात प्रभावित करने वाले स्थानों पर अपने वाहन खड़े न करें।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाली अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नागरिकों से अपील है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें और सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न करें।

सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम की कार्रवाई, 2600 रुपये जुर्माना वसूला



भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार 05 अगस्त 2026 को जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-03 अंतर्गत मॉडल टाउन क्षेत्र के विनोबा नगर के पास विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, अनुज्ञति लाइसेंस का अभाव, इस्टबिन की व्यवस्था नहीं होने तथा साफ-सफाई का अभाव पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान संतोष किराना स्टोर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 700 रुपये,

वर्मा किराना स्टोर पर 700 रुपये सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए तथा 100 रुपये इस्टबिन नहीं रखने पर, मंदू प्रसाद कानू पर 500 रुपये सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर, मंदू प्रसाद कानू आनंद पान पैलेस पर 100 रुपये साफ-सफाई नहीं रखने पर तथा चाय चक्का प्रतिष्ठान पर अनुज्ञति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार निगम की टीम द्वारा कुल 2600 रुपये की चालानी राशि वसूल की गई। निगम प्रशासन ने प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, लाइसेंस प्राप्त करने, आसपास स्वच्छता बनाए रखने, इस्टबिन की व्यवस्था रखने तथा आवश्यक अनुज्ञति लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए।

720 ग्राम के नवजात ने जीती जिंदगी की जंग, 1.4 किलो वजन के साथ स्वस्थ होकर घर लौटा

दुर्ग। कुठेल ग्राम निवासी पत्नी और अतुल साहू के यहां छठे माह में जन्मे महज 720 ग्राम वजन के अति-समयपूर्व नवजात ने एसएनसीयू दुर्ग में दो माह से अधिक समय तक चले गहन उपचार के बाद जिंदगी की जंग जीत ली। दुर्ग जिला अस्पताल में ही जन्मे इस नवजात को जन्म के समय गंभीर श्वसन संकट था। उपचार के बाद आज 1.4 किलोग्राम वजन के साथ सफलतापूर्वक डिस्चार्ज किया गया। एसएनसीयू में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. वाई. किरण कुमार ने जन्म के शुरुआती समय में ही फेफड़ों में सर्फेक्टेंट देकर वेंटिलेटर सपोर्ट शुरू किया। उपचार एसएनसीयू नोडल अधिकारी एवं एंटीबायोटिक्स, कैफरीन, सीपीपीसी सपोर्ट एवं कई बार पीआरबीसी रक्त



वाई. किरण कुमार की निगरानी में चला। इलाज के दौरान नवजात को आवश्यकतानुसार उच्च श्रेणी की एंटीबायोटिक्स, कैफरीन, सीपीपीसी सपोर्ट एवं कई बार पीआरबीसी रक्त

चढ़ाया गया। उपचार के दौरान नवजात में आरओपी (रेटिनोपथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी) विकसित होने पर आंखों में आवश्यक एंटी-वीडोजीफ इंजेक्शन भी दिया गया। नवजात की

केयर (केएमसी) बेहद महत्वपूर्ण है। मां पत्नी द्वारा नियमित केएमसी एवं उपचार में निरंतर सहयोग ने भी नवजात के स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत जीतकर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का गौरव : भाजयुमो बेमेतरा

बेमेतरा। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल-2026 की महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाली राजनंदागांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय वर्मा एवं महामंत्री गौरव यदु ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी की यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है और प्रदेश की युवा शक्ति के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरी है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष विजय वर्मा ने कहा कि अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीतना ज्ञानेश्वरी यादव की वर्षों की कठोर साधना, अनुशासन, आत्मविश्वास और अदम्य इच्छाशक्ति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि समर्थन और निरंतर मेहनत के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। ज्ञानेश्वरी यादव को 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद प्रदान करने की घोषणा राज्य सरकार की खेल एवं



खिलाड़ियों के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाती है। यह निर्णय प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों में नया उत्साह और आत्मविश्वास पैदा करेगा। एशियाई खेल एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का तिरंगा नुलंद करते हुए छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को सम्मान देना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना ही विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री गौरव यदु ने कहा कि मुख्यमंत्री साय ने ज्ञानेश्वरी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उन्हें 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने की घोषणा की। इससे प्रदेश की युवाओं में रुचि बढ़ेगी। गौरव यदु ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्थन के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता हासिल की है।

भिलाई निगम की स्वावलंबन एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची जारी

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत 25 दुकान एवं 08 चबूतरा तथा महिला समृद्धि बाजार योजना के अंतर्गत 06 दुकानों का योजनावार विभिन्न स्थलों पर रिक्र दुकानों का संवर्गवार लॉटर के माध्यम से किरायेदारी पर आबंटन किया जाना है। इसके लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निगम द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून 2026 रखी गई थी। निर्धारित तिथि तक की तिथि में वृद्धि करते हुए 25 जुलाई 2026 तक कर दिया गया था। विस्तारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की सूची दावापति के लिए निगम मुख्यालय के सूचना पटल पर चप्पा कर दी गई है।